छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg No-CHHHIN/2020/87351 वर्ष - 05 अंक - 74 बैकुंठपुर, रविवार 15 दिसम्बर 2024 पृष्ठ -8 मूल्य -1 www.cgfrontline.com

अडाणी पर मेहरबान अधिकारियों ने घाटबर्रा के ग्रामीणों का बढ़ाया आक्रोश

परिसंपत्तियों के विवरण में गंभीर खामियां, ग्रामीणों ने संपत्ति का परीक्षण करने गांव में आकर करने कहा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल परियोजना हेतु न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, उदयपुर, सरगुजा (छ.ग.) द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21 (1) के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु ग्राम घाटबर्रा के प्रकरणों के लिए सूचना-पत्र का प्रकाशन कर 3 दिनों, 11 से 13 दिसंबर तक दावा आपत्ति का सुनवाई किया गया। सूचना प्रकाशित करके प्रभावितों को सूचित किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी उदयपुर के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर निम्नांकित भूमि पर अपने स्वत्व, अर्जित क्षेत्रफल, किस्म भूमि, निहित अंश अथवा क्षतिपूर्ति के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो लिखित में दस्तावेजी प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करें। साथ ही अनुपस्थित रहने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई करके नियमानुसार मुआवजा निर्धारित करने की बात कही गई। भूमि का विवरण, क्षेत्रफल एवं परिसंपत्ति के विवरण की जानकारी का सूचना प्रकाशित होने के बाद ग्राम घाटबर्रा के ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया। ग्रामीणों ने 11 दिसंबर को अनुभागी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम बन सिंह नेताम से मिलकर अपनी परेशानियों से अवगत कराया तथा ग्राम में ही अधिकारी-कर्मचारियों को भेज कर संपत्ति का परीक्षण करने की बात कही, जिस पर एसडीएम ने ग्रामीणों की बात को मानकर 12 एवं 13 दिसंबर को ग्राम घाटबर्रा में ही दावा आपत्ति का आवेदन लिया।

चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि परिसंपत्तियों के विवरण का प्रकाशन में बहुत ज्यादा खामियां हैं। प्रकाशन किए गए सूची में किसी का घर तो किसी का मवेशी छूटा, किसी ने पेड़ों की जानकारी गलत भरने या परिसंपत्ति में उसे शामिल नहीं करने का आरोप लगाया। यहां तक कि ग्राम के सरपंच का परिसंपत्ति का विवरण ही गलत दर्ज था, जिस पर उन्होंने एसडीएम से इनमें सुधार करने की मांग की। ग्राम के अन्य लोगों ने जिस तरह की समस्याएं बताई उनमें भूमि के कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि वर्तमान स्थिति में भूमि पर काबिज कोई और है और मुआवजा प्रकरण किसी और के नाम पर दिख रहा है। कई ऐसे प्रकरण भी सामने आए जिनमें भूमि की रजिस्ट्री के पेपर तो भूमि स्वामियों के पास हैं परंतु उनके वर्तमान बी वन खसरा में पूर्व के जमीन मालिक या किसी अन्य के नाम दर्ज रहे हैं। पारिवारिक बंटवारा के तहत जिन परिवारों में चार लोग हैं चारों के मकान अलग हैं परंतु उनमें सिर्फ एक या दो के ही मकान का विवरण प्रदर्शित हो रहा है, इस पर भी लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है। 100 से अधिक ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें इस तरह की परेशानियां आई हैं और लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करा सुधार की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि अभी तक उन्हें इस बात का पता ही नहीं है क्यों उन्हें विस्थापन कहां दिया जा रहा है, किस गांव में उन्हें विस्थापित करके भेजा जाएगा।

ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। तीन दिनों में यदि पूरे आवेदन जमा नहीं हो पाए तो ग्रामीणों को कुछ और वक्त दिया जाएगा। शासन के नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
बन सिंह नेताम
अनुविभागीय अधिकारी

विधायक दे रहे थे सुशासन की दुहाई, इधर भाजपा नेता भड़के

कलेक्टोरेट के सभागार में सरकार के एक वर्षीय कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड को पत्रकारों से चर्चा

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। कलेक्ट्रेट के सभागार में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा विधायक भैयालाल राजवाड़े ने सरकार के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया है। इधर सुशासन को लेकर चल रहे बखान के बीच भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने भड़ास निकालते हुए प्रधानमंत्री आवास निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते बहुत कुछ कह डाला।

पत्रकारों से चर्चा के दौरान विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश की पहली सरकार है जिसने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में जनता से किए गए वादों को समय पर पूरा किया है। उन्होंने कहा सरकार की योजनाएं और नीतियां समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं लाई गई हैं, जिनसे उन्हें सीधा लाभ मिला है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को रिपोर्ट कार्ड के रूप में पेश किया और कहा कि इस रिपोर्ट कार्ड में सरकार की प्राथमिकताओं और उन पर हुई प्रगति को दिखाया गया है। पिछले एक साल में विकास के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और शिक्षा क्षेत्र में नई योजनाओं का शुभारंभ शामिल है। विधायक ने केंद्र की मोदी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश को नई दिशा और दशा मिली है। विष्णु देव साय के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। भविष्य में कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसको आम लोगों को लाभ मिलेगा। इस दौरान ओम प्रकाश सोनी, दिलीप सोनी, बिहारी पाल, गोपाल कृष्ण मिश्रा के अलावा वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भ्रष्टाचार के आरोपों पर गरमाया माहौल

प्रेस वार्ता के बीच में माहौल उस समय गरमा गया जब भाजपा जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भैयालाल राजवाड़े सरकार के सुशासन और विकास कार्यों की दुहाई देने में लगे थे, इधर की प्रगति की जानकारी दे रहे थे, तभी ओम प्रकाश ने कहा कि वे बलरामपुर जिला मुख्यालय के भनौरा गांव का निरीक्षण करें, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनियमितताएं हुई हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान 61 मकानों को पूरा बताया गया, लेकिन इनमें से 34-35 मकानों का भी निर्माण नहीं हुआ है। कई मकान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। आवास बने ही नहीं और पैसा हड़प लिया गया। इस मामले को जिला पंचायत, जनपद पंचायत, बलरामपुर कलेक्टर, स्थानीय विधायक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल तक पहुंचाने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। हालांकि, भाजपा नेता मामला अखबार की सुर्खियां न बने, इसका प्रयास करते अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में जांच हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

उप स्वास्थकेंद्र लक्ष्मणगढ़ बंद, मरीज हो रहे परेशान

छ.ग.फ्रंटलाइन उदयपुर। सरगुजा जिले के उदयपुर मुख्यालय के ग्राम लक्ष्मणगढ़ स्थित उप स्वास्थ केंद्र हमेशा बंद रहता है, जिससे आसपास के गांव के मरीजों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र सेक्टर लक्ष्मणगढ़ के आसपास के ग्राम मानपुर, महेशपुर, फुनगी, सानीबर्रा, सुखरीभंडार, सेमीघोघरा, तेंदूटिकरा के लोगों ने बताया कि गांव के मरीज जब भी स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणगढ़ पहुंचते हैं तो वहां ताला जड़ा रहता है, जिससे उन्हें 10 किलोमीटर की दूरी अलग से तय करनी पड़ती है। मरीजों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यह रवैया एक वर्ष से लगातार चल रहा है। महीने में दो-चार दिन ही उप स्वास्थ्य केंद्र खुलता है, बाकी समय हमेशा ताला बंद रहता है। एक वर्ष पहले भी अस्पताल बंद पाए जाने पर ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर नदारत रहने का आरोप लगाया था। कहना है कि उदयपुर स्वास्थ्य विभाग व बीएमओ की मिलीभगत से पिछले बार जांच मं कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक महीने ड्यूटी के प्रति तटस्थता दिखाने के बाद फिर से स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में ताला बंद करके गायब रहने लगे हैं।

मरीज नीमहकीम या निजी चिकित्सक के यहां जाने विवश

शनिवार को ग्राम लक्ष्मणगढ़ के राजेंद्र प्रसाद बिंझिया लगभग 2 बजे बच्चे और बीमार पत्नी को लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणगढ़ पहुंचे तो अस्पताल में ताला बंद मिला। जिम्मेदारों का फोन भी नहीं लगा, जिससे उन्हें निराश होकर 10 किलोमीटर दूर सीएससी उदयपुर जाना पड़ा। आगरसाय भी उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला बंद मिलने पर निराश होकर घर वापस लौट गया और नीमहकीम से इलाज कराया। सोनेलाल अपनी बुजुर्ग मां का तबियत खराब होने पर उप स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणगढ़ पहुंचा, तो स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा था। अस्पताल के कर्मचारियों से फोन पर संपर्क नहीं हुआ। बाद में वह उदयपुर से प्राइवेट डॉक्टर को बुलवाकर अपनी मां का इलाज कराया। अस्पताल में आरती सिंह, गोमती सिंह व अनीता राजवाड़े कर्मचारी हैं, जिसमें से एक को हमेशा अस्पताल में रहना है लेकिन अस्पताल बंद मिलता है, जबकि दीवार में खुलने का समय सारणी 10.30 से 5.30 तक उल्लेखित है।

गैर जिम्मेदारों को हटाया जाए-शिवभजन

ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ के सचिव शिव भजन सिंह से बात करने पर वह बताया कई बार अस्पताल बंद रहने का शिकायत आ चुका है। आज भी सुबह से अस्पताल बंद है। ड्यूटी नहीं करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरे कर्मचारियों की पदस्थापना होनी चाहिए।

वार्डों का आरक्षण 19 दिसंबर को

छ.ग.फ्रंटलाइन जरही/भटगांव। सूरजपुर के नगरीय निकायों नगर पालिका परिषद् सूरजपुर, नगर पंचायत जरही, नगर पंचायत भटगांव, नगर पंचायत विश्रामपुर, नगर पंचायत प्रतापपुर के वार्डों का आरक्षण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण 1994 के प्रावधानों के तहत 19 दिसंबर को जिला कार्यालय सभाकक्ष में संपन्न कराया जाना है, जिसका समय नगर पालिका परिषद सूरजपुर का 12.30 से 1.30 बजे तक, नगर पंचायत जरही का 1.30 से 2.30 बजे तक, नगर पंचायत भटगांव का 2.30 से 3.30 बजे तक, नगर पंचायत बिश्रामपुर का 3.30 से 4.30 बजे तक, नगर पंचायत प्रतापपुर का 4.30 से 5.30 बजे तक निर्धारित है। जिले के सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों से उक्त तिथि को निर्धारित समय में उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा है।

पत्नी के हत्या के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। हत्या के मामले में बतौली थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके घटना में प्रयुक्त लकड़ी का फारी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक 8 दिसम्बर को रात करीब 8 बजे सनमुनी नामक महिला के साथ घर के बाहर पति ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें उसे सिर में अन्दरूनी चोट आई थी। ईलाज दौरान सीतापुर अस्पताल में वह दम तोड़ दी थी। सीतापुर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही थी। घटनास्थल जॉच दौरान पुलिस ने पाया कि 08 दिसम्बर की रात को पहल राम अपनी पत्नी मृतिका सनमुनी से शराब पीने के लिए पैसा मांगा, लेकिन वह इंकार कर दी। रुपये नहीं देने के कारण आरोपी पति ने अपनी पत्नी सनमुनी के साथ मार पीट की घटना को अंजाम दिया था और उसके सिर को दिवार से टकरा दिया। इसके बाद लकड़ी के फारी से चेहरा एवं कंधा में चोट पहुंचाया था, 10 दिसम्बर को सीतापुर अस्पताल में महिला की मौत हो गई। मामले में प्रार्थी राम कोरवा की रिपोर्ट पर थाना बतौली में धारा 103(1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी पहल राम पिता स्व. बंधन राम 40 वर्ष निवासी बिरीमकेला पटेलपारा को गिरफ्तार करके पुलिस पूछताछ की और लकड़ी के फारी को जप्त किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक अशोक शर्मा, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, आरक्षक राजेश खलखो, मुरलीधर यादव, देवनाथ भगत, नवीन खलखो, भगलू राम पैंकरा एवं महिला आरक्षक मेरी क्लारेट तिर्की शामिल रहे।

कीटनाशक का सेवन किए युवक की मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। बलरामपुर जिला के सनावल थाना अंतर्गत ग्राम इंद्रावतीपुर निवासी शत्रुघन पिता रामबितल खैरबार 20 वर्ष की कीटनाशक का सेवन करने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया मृतक 12 दिसम्बर की रात को शराब का सेवन करने के बाद कीटनाशक का अज्ञात कारणों से सेवन कर लिया था। स्वजन उसे सनावल स्वास्थ्य केन्द्र लेकर गए, यहां से रेफर करने पर बलरामपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। 13 दिसम्बर को यहां से भी चिकित्सकों ने आवश्यक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में उपचार के दौरान शुक्रवार की शाम को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है।

ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय को लेकर सरकार का कराया ध्यानाकर्षण

प्रदेश आह्वान पर ओबीसी महासभा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ शासन, उपमुख्यमंत्री अरुण साव व नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष व सरगुजा संभाग के प्रभारी परशु राम सोनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधमंडल सुभाष साहू, प्रदेश सचिव ओबीसी महासभा, आदित्य गुप्ता जिला कार्य समिति सदस्य के अलावा सत्यनारायण वर्मा, कृष्णा सोनी, राम अवतार गुप्ता, रघुनंदन, युगल किशोर, विकास ठाकुर, राजेश सहित ओबीसी महासभा के कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अधिकांश संभाग व जिलों में ओबीसी की जनसंख्या 27 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद उन्हें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण न देकर अधिकतम 27 प्रतिशत आरक्षण का सीमित प्रावधान किया गया है, जो बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय व असंवैधानिक है। तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल जैसे राज्यों में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में 50, 49 और 40 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 27 प्रतिशत आरक्षण राज्यपाल के पास लंबित है, उसको अभिलंब पास कर पिछड़ा वर्ग के हित में कार्य किया जाना चाहिए। राज्य सरकार से उक्त तथ्यों एवं उल्लेखित तीनों राज्यों के आरक्षण व्यवस्था के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्व कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया गया है। ओबीसी महासभा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ओबीसी समाज के हित में अगर विधेयक पारित नहीं होने पर ओबीसी महासभा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी।

होली क्रॉस वीमेन्स कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स मीट संपन्न

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। होली क्रॉस वीमेन्स कॉलेज में महाविद्यालयीन प्राचार्य के निर्देशन में एनुअल स्पोर्टस मीट-2024-25 के अंतर्गत विभिन्न खेलों के निर्णायक मैच का आयोजन, सम्पन्न हुआ। स्पोर्टस मीट के अंतर्गत महाविद्यालय में अध्यनरत छात्राओं में खेल प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से 5 दिसम्बर से महाविद्यालय के खेल मैदान में विभिन्न खेलों ने छात्राएं प्रतिभागी हुई।

फाइनल मैच का प्रारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सिस्टर शाता जोसेफ के द्वारा गेंद को हवा में उछालकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल की भावना को जीवंत रखने का संदेश देते हुए कहा कि खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जिससे कार्यशक्ति विकसित होती है। आयोजन में बास्केटबॉल का फाइनल मैच बीकॉम भाग दो व बीएससी भाग तीन, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, गणित, कंप्यूटर साइंस विषय की छात्राओं की बनी टीम के बीच खेला गया, जिसमें बीएससी भाग तीन की छात्राएं विजेता रही। खोखो का फाइनल मैच में बीएससी भाग दो गणित, कंप्यूटर साइंस विषय व बीएससी भाग दो बॉटनी विषय के बीच खेला गया, जिसमें बीएससी भाग दो की छात्राएं विजयी रहीं। हैंडबॉल का फाइनल मैच बीएससी भाग एक इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, गणित, कंप्यूटर साइंस विषय की छात्राओं व बीएससी भाग 3 बॉटनी विषय की छात्राओं की टीम के बीच खेला गया, जिसमें बीएससी भाग एक की छात्राएं विजेता रहीं। खेल आयोजन में स्कोरर अंजना, मैच रेफरी विक्की विक्टर, कॉमेंट्रेटर एसएस अली रहे। मंच संचालन आलोक चक्रवर्ती ने किया। सभी खेल महाविद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अनुदेशक राधा खलखो के पर्यवेक्षण में संपादित हुआ। खेल आयोजन में महाविद्यालय की छात्राओं का उत्साह पूरी उर्जा से ओतप्रोत रहा। इस अवसर पर महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉ. सिस्टर मंजू टोप्पो सहित महाविद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी व छात्राओं की उपस्थिति रही।

प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ भाग रहे तस्कर को घेराबंदी करके पकड़ी पुलिस

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में गांधीनगर थाना पुलिस ने 01 आरोपी के पास से 80 नग प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन जप्त किया है। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जप्त प्रतिबंधित इंजेक्शन की कीमत लगभग 50 हजार रुपये है। जानकारी के मुताबिक 13 दिसम्बर को थाना गांधीनगर पुलिस टीम पेट्रोलिंग में निकली थी, इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पेट्रोलिंग वाहन को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने उसे घेराबंदी करके महुआपारा चर्च ग्राउंड बर्मा बाड़ी से पकड़ा और हाथ में रखे झोले रखा इंजेक्शन बरामद किया। पूछताछ में आरोपी भूषण बेक 30 वर्ष निवासी महुआपारा थाना गांधीनगर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। आरोपी के विरुद्ध धारा 22 (सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, सहायक उप निरीक्षक राकेश मिश्रा, आरक्षक अतुल सिंह, बृजेश राय, अरविंद उपाध्याय, मनीष सिंह, ऋषभ सिंह सक्रिय रहे।

पॉलीटेक्निक कॉलेज विश्व एड्स दिवस पखवाड़ा के तहत विविध आयोजन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में विश्व एड्स दिवस पखवाड़ा के तहत छात्र-छात्राओं को एचआईवी, एड्स के संबंध में मुख्य अतिथि डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता जिला नोडल अधिकारी एचआईवी, एड्स एवं क्षयरोग सरगुजा ने बताया। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी मंगल पाण्डेय एवं प्राचार्य आरजे पाण्डेय के अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। अतिथियों ने विश्व एड्स दिवस के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक बीमारी से संबंधित जानकारी दी। प्राचार्य आरजे पाण्डेय ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि आज के कार्यक्रम की सार्थकता तब सिद्ध होगी जब हम सभी स्वयं जागरूक होंगे और अपने आस-पास के लोगों को एचआईवी, एड्स, क्षयरोग एवं यौन जनित रोग तथा नशे की लत से दूर रहने के लिए जागरूक करेंगे।

नवगठित नपं शिवनंदनपुर के विकास में नहीं होगी कमी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। विधानसभा चुनाव में हमने नारा दिया था कि हम बनाए हैं हम ही संवारेंगे। इसी तर्ज पर नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर का गठन जब भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, तो इसके विकास में किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। भाजपा की साय सरकार के एक वर्ष पूरे हो गए हैं। साय सरकार द्वारा सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए विकास कार्य किए जा रहे हैं। उक्त बातें क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने शनिवार को नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर कार्यालय प्रांगण में संचालन समिति के पदाधिकारियों के आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि की आसंदी से व्यक्त करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यहां पर क्षेत्रवासियों का लंबे अरसे से नगर पंचायत बनाए जाने का मांग था, जिस पर पिछले दिनों सुरजपुर जिला प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मेरे द्वारा शिवनंदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी और मुख्यमंत्री द्वारा मंच से तत्काल स्वीकृति देते हुए

घोषणा कर दी गई थी। इसी के फलस्वरूप आज क्षेत्रवासियों का सपना पूरा हो सका है। क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से हमने यह कार्य पूर्ण करने में सफलता प्राप्त की है। अब यहां पर तेजी से विकास कार्य को गति प्रदान की जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े समेत अन्य अतिथियों में पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा, पूर्व भटगांव विधायक रजनी रविशंकर त्रिपाठी, बिश्रामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष आशीष यादव, अनिल मिश्रा, चरण सिंह अग्रवाल, मुरली सोनी, बनारसी जायसवाल, संदीप अग्रवाल, शशिकांत गर्ग, ललित गोयल, दीपेंद्र सिंह चौहान, राजेश यादव, श्यामा पांडेय, रमेश दनौदिया, चंदन सिंह, अशोक अग्रवाल शोक्की, संजीत सिंह, रितेश जायसवाल, विजयराज अग्रवाल, शिवनंदनपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष देवधन राम बिंझिया, विकास सिंह का स्वागत किया गया। अतिथियों द्वारा भारत माता व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर के संचालन समिति के अध्यक्ष कृष्णा गोयल, उपाध्यक्ष श्यामू साहू समेत सदस्य शितीकांत स्वाई, धर्मेंद्र गुप्ता, मनी बग्गा, अनीता सिंह, प्रमिला साहू को सुरजपुर एसडीएम शिवानी जायसवाल द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह को अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित कर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान मनमत बछाड, भोला सिंह, अमरलाल साहू, पवन अग्रवाल पोनी, सुशील जैन, मोहिनी झा, चिंटू खेड़ा, संजय चौधरी, रिंकू गोयल, शैलेश सिंह, शशि नान्हू, जतिन तायल, रोमी खेड़ा, बंटी जायसवाल, विवेक जायसवाल, रिशु अग्रवाल, राजू जिंदल, अनिल गर्ग के अलावा एडिशनल एसपी संतोष महतो, लटोरी तहसीलदार सुरेंद्र पैकरा, पिलखा नायब तहसीलदार मीना सिंह, नगर पंचायत शिवनंदनपुर के सीएमओ सुशील कुमार तिवारी, पंचायत सचिव धनेश्वर प्रजापति, ललन, गुप्तेश्वर गुप्ता व अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में मंच संचालन गौरीशंकर पांडेय ने किया।

छात्रा का हुआ सम्मान

नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर में संचालन समिति के शपथ ग्रहण समारोह में अतिथियों द्वारा नगर के मेधावी छात्रा चारुल गर्ग को सीजीपीएससी में 36 वा रैंक प्राप्त करने के फलस्वरूप स्मृति चिन्ह व शॉल श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। चारुल गर्ग नगर के अनिल गर्ग की पुत्री हैं, जो इसी वर्ष यह उपलब्धि हासिल की है।

कैलाशपुर में चलित थाना लगाकर दी गई कानूनी जानकारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर के निर्देश पर आज जयनगर पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत कैलाशपुर में चलित थाना लगाकर आमजन को कानूनी जानकारी दी गई। शनिवार को जयनगर थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत कैलाशपुर में चलित थाना लगाया गया। यहां पर थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को कानूनी जानकारी देते हुए कहा कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में आमजन की मदद जरूरी होती है। पुलिस जब तक आमजन से बेहतर सामंजस्य स्थापित नहीं करेगी तब तक अपराध पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। थाना प्रभारी ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता लागू करके आमजन को काफी अधिक अधिकार दिए गए हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। थाना प्रभारी द्वारा यहां पर लोगों को साइबर अपराध, नशा से दूर रहने, वाहन चलाते समय सतर्कता बरतने व यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही यह भी आह्वान किया गया कि क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को देवें। थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में घूमने वालों से अपने गहने की सफाई भी न कराएं, जिससे ठगी का शिकार होने से बच सकें। इस दौरान प्रधान आरक्षक राजेंद्र, महिला नगर सैनिक अनीता व अन्य ग्रामीणजन उपस्थित थे।

19 दिसम्बर को होगा नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के वार्डों का आरक्षण

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत निर्वाचन 2024 के लिए वार्डों का आरक्षण किया जाना है। जिसके तहत कलेक्टर एवं आरक्षण विहित प्राधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा द्वारा जिले के नगर पालिका परिषद बलरामपुर एवं नगर पंचायत रामानुजगंज, राजपुर, कुसमी तथा वाड्रफनगर के लिए आरक्षण तिथि एवं समय निर्धारित किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी सूचना के तहत नगर पालिका बलरामपुर के 15 वार्डों एवं चारों नगर पंचायतों के 60 वार्डों के लिए आरक्षण 19 दिसम्बर 2024 को प्रात: 11 बजे संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में किया जाएगा। उक्त आरक्षण की प्रक्रिया में जो नागरिक उपस्थित रहना चाहते हैं वे निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रह सकते हैं।

घर घर बाबा श्याम की ज्योत जलाने किया जा नि:शुल्क कीर्तन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। घर घर बाबा श्याम की ज्योत जले इस ध्येय से श्री श्याम दीवाने टोली सरगुजा संभाग खाटू वाले बाबा श्याम का गुणगान 13 महीनों से नि:शुल्क कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं। नि:शुल्क कीर्तन का आयोजन सरगुजा संभाग के ऐसे जगहों पर किया जा रहा है, जहां के लोग कलयुग के अवतार खाटू वाले श्याम को नहीं जानते हों और न कभी एक बार भी ऐसे जगहों पर कीर्तन हुआ हो।टोली के सदस्यों ने बताया कि टोली में सरगुजा संभाग के 34 सदस्य हैं, जिनके सहयोग से प्रतिमाह नि:शुल्क अरदास कीर्तन का आयोजन होता है। इस कीर्तन में भारत के विभिन्न राज्यों के भजन प्रवाहक अपनी भजनों की प्रस्तुति देते हैं। श्री श्याम दीवाने टोली का मुख्य उद्देश्य घर घर बाबा श्याम का बखान करना है और हारे हुए लोगों को बाबा श्याम से जोड़ना है। इसी बात के उद्देश्य से टोली ने अब तक सरगुजा संभाग के 13 जगहों पर कीर्तन कर चुकी है। टोली द्वारा नि:शुल्क बस यात्रा से उड़ीसा स्थित भटली धाम का भी दर्शन कराया जा चुका है। आने वाले समय में टोली द्वारा खाटूधाम दर्शन हेतु नि:शुल्क सेवा दी जाएगी। श्री श्याम दीवाने टोली द्वारा अब तक प्रेमनगर, अजबनगर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, पटना, शंकरगढ़, बतौली, लटोरी, रघुनाथपुर व अन्य जगहों पर बाबा श्याम का कीर्तन किया जा चुका है।

शिक्षा के मंदिर के पास ही नशेड़ी फेंक रहे शराब की बोतल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। नगर पंचायत बिश्रामपुर क्षेत्र के प्राथमिक शाला ग्लोब स्कूल व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शिवनंदनपुर भवन के समीप शराब की बोतल होने से आमजन में नाराजगी व्याप्त है। अव्यवस्था ने स्वच्छता अभियान की कलई भी खोलकर रख दी है।

गौरतलब है कि नगर पंचायत बिश्रामपुर क्षेत्र के प्राथमिक शाला ग्लोब स्कूल व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शिवनंदनपुर भवन के समीप नशेडियों द्वारा प्रतिदिन शराब

की बोतलों को करीब 20 मीटर की दूरी पर फेंक दी जाती है। ऐसी स्थिति में यहां पर अध्ययन करने आने वाले छात्रों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि स्वच्छता अभियान के नाम पर शासन द्वारा यूं तो लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं लेकिन मैदानी स्तर पर स्थिति कुछ और ही बयां करती दिखाई पड़ रही है। स्वच्छता एजेंसी द्वारा यहां पर साफ सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जा रहा है। आमजन द्वारा संबंधित अधिकारियों से शिक्षा के मंदिर के आसपास बेहतर साफ सफाई कराए जाने की मांग की गई है।

रामानुजगंज नगर पंचायत क्षेत्र का मामला

पुलिस ने नौ संदिग्धों पर की कानूनी कार्रवाई

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

रामानुजगंज। सरहदी क्षेत्र रामानुजगंज के नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में रह रहे संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए नौ लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में संदिग्ध लोगों के खिलाफ चलाई गई अभियान में पुलिस को नौ लोग ऐसे मिले जिनके पास निवास से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं मिला। तत्पश्चात पुलिस ने उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए बीएनएसएस कि धारा 128 के तहत दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस विभाग द्वारा इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन-किन वार्डों से उनका चयन किया गया और किनके मकान में किराए से रह रहे थे क्योंकि किसी भी वार्ड में यदि ऐसे लोग निवास कर रहे हैं तो उस वार्ड पार्षद की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह कानून को इस बात की जानकारी दें की किनके

मकान में संदिग्ध लोग रह रहे हैं यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधि कानून व्यवस्था में सहयोग नहीं करेंगे तो अपराधों को रोका जाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है प्राय: रामानुजगंज नगर पंचायत क्षेत्र में निवास रत मकान मालिक बाहरी व्यक्तियों को किराए में मकान तो उपलब्ध करा देते हैं लेकिन उनसे संबंधित दस्तावेज कभी भी पुलिस विभाग को उपलब्ध नहीं करा पाते शासन प्रशासन द्वारा यदि समय-समय पर कड़ी कार्रवाई की जाए तो नगर में किराए के दुकान एवं मकान चलने वाले पहले संबंधित विभाग को जानकारी उपलब्ध कराने के बाद ही उनको मकान या दुकान उपलब्ध कराते लेकिन यहां सब भौसा पूरी कारोबार चल रहा है इसी का परिणाम है कि रामानुजगंज में कई नए चेहरे दुकानों एवं मकान में नजर आते हैं। वैसे पुलिस विभाग के द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि दुकान एवं मकान किराए में लगाने से पहले उनसे संपूर्ण दस्तावेज प्राप्त कर पुलिस विभाग को भी उपलब्ध कराया जाए ताकि कभी भी घटना दुर्घटना होने पर जांच पड़ताल करने में आसान हो।

स्वास्थ्य संवेदना समिति ने दिवंगत कर्मचारी के परिजनों को दी सहायता राशि

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के संवेदनशील स्वास्थ्य कर्मचरियों द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य संवेदना समिति सूरजपुर के योजनांतर्गत विकासखंड प्रतापपुर में ड्राइवर के पद पर पदस्थ रहे स्व. चंद्रभाषकर पटेल के पिता को पच्चीस हजार रुपए का चेक समिति के अध्यक्ष इंद्रसेन विश्वकर्मा व कोषाध्यक्ष अमित चौरसिया सहित समिति के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिवंगत कर्मचारी के गृहग्राम जाकर प्रदान किया गया द्य स्वास्थ्य संवेदना की जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष श्री विश्वकर्मा ने बताया गया कि समिति द्वारा अपने सदस्यों के लिए उनके और उनके आश्रित परिजन के दुर्घटना या गंभीर बीमारी में उपचार के लिए तथा सदस्य की आकस्मिक निधन पर सहयोग संवेदना राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाती है। सूरजपुर जिले का कोई भी नियमित अनियमित स्वास्थ्य कर्मचारी प्रतिवर्ष एक हजार का सहयोग राशि देकर सदस्यता ले सकता है।

विभिन्न मांगो को लेकर गोंगपा ने निकाली रैली किया थाने का घेराव

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के चांदनी बिहारपुर में शुक्रवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने रैली निकाल थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बाद में अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है।ज्ञापन में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 का पालन किया जावें। यह कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वचन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, 2007 एवं संसोधित अधि 1नियम 2012 के तहत किसानों को पटटा प्रदान किया जाना था, किन्तु आज भी प्रत्येक गांव में सैकडो किसानों को विधिवत पटटा प्रदान नहीं किया गया है, ग्राम समा से पात्र किये गये सभी किसानों को पटटा प्रदान किया जावें।अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006-07 के तहत कुछ किसानों को वन अधिकार पत्रक प्रदान किया गया है, लेकिन ग्राम व

कान्तिपुर, कोल्हुआ, खोहिर, रामगढ़, उमझर, छतरंग, खरहरिजोर, बांक एवं लांजित की किसानो को किसान-किताब प्रदान नहीं किया गया है, जिससे किसानों को किसान किताब प्रदान किया जावें। वर्ष 2017 से ही जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम खैरा के लगभग 18 किसानों की भूमि को नहर निर्माण हेतु अधिग्रहित कर लिया गया है, किन्तु आज तक किसानों को मुआवजा राशि अप्राप्त है। सभी किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जावें। समस्त धान खरीदी केन्द्रो में किसानों से निर्धारित मात्रा से प्रत्येक बोरी में 1/2 से 1 किलो अतिरिक्त धान लिया जाता है जिसकी जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही किया जावे। धान खरीदी केन्द्रों में प्रबंधको द्वारा हमाली का मजदूरी किसानों से ही भुगतान कराया जाता है, जिसकी जांच एवं दोषियों पर उचित कार्यवाही किया जावें।ग्राम सपहा निवासी सोमारी पण्डो द्वारा 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व से वन भूमि में काबिज लगभग 2.50 एकड़ का पटटा प्रदान किया जावें। यह कि जनपद पंचायत सूरजपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत शर्मा में सरपंच एवं सचिव द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितता किया।गया है जिस पर कई बार आवेदन किया गया है लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं होने से ग्रामवासियों में व्यापक आक्रोश है जिसकी जांच एवं उचित कार्यवाही किया जावें। ग्राम पंचायत सपहा निवासी शिवचरण सिंह पोर्ते को थाना में पवन सिंह के द्वारा बुलाकर बेवजह का गाली गलौच व धक्का मुक्की कर अपमानित किया गया जिसकी जांच कर दोषियो पर कार्रवाई की मांग की गई है।

सड़क पर चलना हो गया था दुभर विधायक ने किया पहल कर वित्त विभाग से दिलवाया स्वीकृति

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

प्रतापपुर। विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के प्रयास से प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच विहीन सड़क की नवीनीकरण व नई सड़क के काम के लिए राशि स्वीकृत कराई गई है।

जानकारी के अनुसार चंदौरा से जजावल मार्ग जो काफी जर्जर हो गया था सड़क खराब होने की वजह से आम जनों को बहुत परेशानी हो रहा था जिसे ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने चंदौरा से जजावल मार्ग के नवीनीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 14 किलोमीटर सड़क के लिए 892.50 लाख राशि वित्त विभाग में स्वीकृत कर दिया है वहीं और एक सड़क जो बरसों से निर्माण के लिए इंतजार किया जा रहा था जो जजावल से परमेश्वरपुर घाट कटिंग सहित 10 किलोमीटर सड़क के लिए लोक निर्माण विभाग ने 1508.94 लाख रुपए वित्त विभाग में स्वीकृत कर दोनों कार्यों का निविदा जारी किया है इन कार्यों की स्वीकृति से क्षेत्र वासियों वर्ष व्याप्त है क्षेत्रवासियों ने विधायक का धन्यवाद किया है वहीं विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने चर्चा के दौरान कहा की उक्त दोनों सड़क बहुत खराब स्थिति थी क्षेत्र भ्रमण के दौरान की बार शिकायत मिल चुकी थी चुनाव से पहले मैं इन क्षेत्रों में आना जाना करती थी उस दौरान मैंने कहा था मैं जैसे चुनाव जीतुगी इन सड़कों का नव निर्माण के लिए प्रयास करुंगी और अब इसका स्वीकृति मिल गया है इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव का धन्यवाद करती हु।

पोषण सखियों का हुआ तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र में आयोजित किया गया कार्यक्रम

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा 15 जिलों के 27 विकासखण्डों के एक हजार ग्रामो में निवासरत ग्रामीण आदिवासी परिवारों के आय वृद्धि एवं वर्षभर पोषित आहार की उपलब्धता हेतु वर्ल्ड बैंक एवं आई.एफ.ए.डी. के सहयोग से ''चिराग परियोजना'' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना अंतर्गत चिन्हांकित ग्रामों में पोषण आधारित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ''पोषण सखी'' के रूप में कार्य करने के लिये ओड़गी विकास

खण्ड संबंधित 40 ग्रामों से महिलाओं का चयन किया गया है। चयनित महिलाएं ''पोषण सखी'' के रूप में कार्य करने के लिये तकनीकि सहयोगी संस्था पी.सी.आई. इंडिया के सहयोग से ओड़गी विकास खण्ड के पोषण सखियों का तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत संसाधन केन्द्र में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान 31 चयनित "पोषण सखी" महिलाओं को चिराग परियोजना का परिचय, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन हेतु संचार का परिचय, सहभागीता को सुगम बनाने, कुपोषण, संतुलित आहार, कृषि एवं पोषण में संबंध, खाद्य प्रणाली, खेती मे विविधता, जंगल और प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा दैनिक भोजन में आहार विविधता के लिये सामाजिक व्यवहार परिवर्तन हेतु संचार किये जाने के लिये मास्टर ट्रेनर पिन्टू ठाकुर और रूपनाथ पीसीआई इण्डिया से एवं श्रीमति सीमा सुपरवाईजर, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

इस अवसर पर उप संचालक कृषि विकास अधिकारी सुश्री संपदा पैंकरा, सहायक संचालक कृषि दुरेश साय पैंकरा एवं संदीप सिन्हा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह एवं जमुना सिंह, आशीष साहू, सतीश राठीया ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विभाग उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ संवाद-42449/14

Created by Universal Document Converter

सम्पादकीय

उपासना स्थल कानून का सभी करें सम्मान

उपासना स्थलों से संबंधित मामले पर सुनवाई या कोई आदेश पारित न करने की हिदायत अदालतों को देकर सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक विवादों पर विराम लगा दिया है। हाल के दिनों में अनेक उपासना स्थलों से जुड़े मामले के कोर्ट पहुंचने के बाद से सांप्रदायिक सदभाव को धक्का लगने की आशंका बढ़ गई है। शीर्ष अदालत ने देश की सभी अदालतों को धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों और दरगाहों पर दावा करने संबंधी नए मुकदमों पर विचार करने और लंबित मामलों में कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से अगले आदेश तक रोक दिया। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट कहा कि क्योंकि मामला शीर्ष अदालत में विचाराधीन है, इसलिए पीठ समझती है कि अगले आदेश तक कोई नया मुकदमा दर्ज न किया जाए। उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश से विभिन्न हिंदू पक्षों द्वारा दायर लगभग 18 मुकदमों में कार्यवाही पर रोक लग गई है। इन मुकदमों में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद समेत 10 मस्जिदों की मूल धार्मिक प्रकृति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया है। वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा वर्ष 2020 में दायर मुख्य याचिका में उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी है। कहा गया है कि उपासना स्थल कानून संविधान के धर्मनिरपेक्षता और बराबरी जैसे मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, इस कानून से हिंदुओं को अधिक नुकसान पहुंचता है। इस याचिका का विरोध करते हुए जमियत उलेमा-ए-हिंद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया और कई एक्टिविस्ट्स ने भी अपनी याचिकाएं दाखिल की थीं। जब देश में अयोध्या विवादित ढांचा को लेकर आंदोलन अपने चरम पर था, तो 18 सितंबर 1991 को केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उपासना स्थल क़ानून संसद से पारित कराया था। उपासना स्थल क़ानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस क़ानून के सेक्शन 3 में वर्णित है कि इस कानून के तहत, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल या किसी समुदाय के पूजास्थल के स्वरूप को बदलने की कोशिश नहीं कर सकता। सेक्शन 4 (2) में लिखा है कि अगर किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव को लेकर कोई केस, अपील, या अन्य कार्रवाई 15 अगस्त 1947 के बाद किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, या प्राधिकरण में लंबित है, तो वह केस रद कर दिया जाएगा। ऐसे किसी मामले में दोबारा केस या अपील दायर नहीं की जा सकती। इस कानून में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि यह मामला आज़ादी से पहले ही अदालत में लंबित था। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान मई 2022 में अहम मौखिक टिप्पणी में कहा था कि प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991 (उपासना स्थल क़ानून) 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार, किसी भी संरचना के धार्मिक चरित्र की जांच करने पर रोक नहीं लगाता है। इसके बाद से ऐसे मामले अदालतों में बढ़ने लगे। दरअसल, उपासना स्थल विवाद को बढ़ावा देना बर्र के छत्ते में कंकड़ मारने जैसा है। उपासना स्थल विवाद खत्म होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश पर रोक लगाकर उपासना स्थल विवादों पर फिलहाल विराम लगाने की कोशिश की है। नए आदेश आने तक सभी को उपासना स्थल कानून का सम्मान करना चाहिए।

विशेष

विष्णुदेव साय

सफल और सार्थक सरकार का एक वर्ष

अंत्योदय' के लक्ष्य के साथ हमारी सरकार ने अपने पंचवर्षीय कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया। यह सब आपके सहयोग और विश्वास के बूते संभव हो सका। पहले लोकसभा और हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव की हमारी जीत ने इस विश्वास पर मुहर लगाई है कि छत्तीसगढ़ सरकार पर जनता का भरोसा बना हुआ है। गर्व से भरी खुशी यह भी है कि एक राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रदेश की जनता जनार्दन का कोटि-कोटि अभिनंदन..! हम सब मिलकर धान का कटोरा कहे जाने वाले अपने राज्य छत्तीसगढ़ को धन-धान्य से परिपूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे, यही संकल्प है।

बीते वर्ष दिसंबर माह में जब मैंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी तो हमारे समक्ष 'मोदी की गारंटी' को पूरा करने की चुनौती थी। सरकार का खाली खजाना हमें विरासत में मिला था लेकिन कुशल आर्थिक नीतियों और प्रबंधन के बलबूते हमने सभी बड़े वादों को पूरा कर दिखाया है। प्रदेश की आधी आबादी यानि मातृ शक्ति को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने का वादा पूरा करते हुए हमने सर्वप्रथम महतारी वंदन योजना लागू की। जिसके अंतर्गत 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की राशि प्रदान कर राज्य की माताओं-बहनों के सम्मान को बढ़ाया है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु छत्तीसगढ़ प्रवास पर आईं तो वे इस योजना की लाभार्थी महिलाओं से रूबरू हुईं और कहा कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे राज्य के अन्नदाताओं जो गारंटी दी थी, उस गारंटी को पूरा करते हुए हमने राज्य के 13 लाख किसानों का दो साल का बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का भुगतान अपनी सरकार के गठन के एक पखवाड़े के भीतर ही कर दी थी। किसान भाईयों के बैंक खाते में बोनस की यह राशि छत्तीसगढ़ के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म-जयंती 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर उन्हें हमने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की थी। प्रधानमंत्री जी की गारंटी के अनुरूप हमने राज्य के किसान भाईयों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी बीते खरीफ सीजन से ही कर रहे हैं। हमने अपने संकल्प को पूरा करते हुए किसान भाईयों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से भुगतान भी कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि हम अपने किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य दे रहे हैं। बीते खरीफ सीजन में 145 लाख मेट्रिक टन धान की हमने रिकॉर्ड खरीदी की है। इस साल भी 14 नवंबर से धान की खरीदी जारी है। राज्य में इस साल खरीफ की अच्छी फसल हुई है। धान खरीदी इस साल हम एक और नया रिकॉर्ड बनाएंगे।

राज्य में पूववर्ती सरकार ने अपनी कार्यशैली से 'भरोसे का बहुत बड़ा संकट' पैदा कर दिया था। बीते एक सालों में हमने जनहितैषी कामों से जनता जनार्दन का भरोसा जीता है। जनता में एक नया विश्वास जगा है। विकास का वातावरण निर्मित हुआ है। हमने बनाया था : हम ही संवारेंगे' के लक्ष्य के साथ हमारी सरकार जनता-जनार्दन की सेवा में लगी है। राज्य की जनता जनार्दन ने हमें सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी तो हमारे इरादे स्पष्ट थे कि सरकार शासन से सुशासन की ओर चलेगी। हमने युवाओं के सुनहरे भविष्य की राह आसान करते हुए 9000 से अधिक रिक्त पदों पर सरकारी भर्ती प्रारंभ की है। पीएससी के ताजा परीक्षा परिणामों ने प्रदेश के युवाओं में नए विश्वास और उत्साह का निर्माण किया है। 10 हजार करोड़ की राशि से चार नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। नगरीय निकायों और पंचायतों में आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला कर हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चलाने में सभी वर्गों की समान भागीदारी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश को माओवाद-मुक्त बनाने के लिए संकल्पित है। इसी दृष्टि बस्तर क्षेत्र में प्रस्तावित 66 सुरक्षा कैंप में से 42 की स्थापना की जा चुकी है। लाल आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने की

नीति के अनुसार अब तक 213 माओवादियों को मार गिराया गया, 937 नक्सली गिरफ्तार हुए एवं 812 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर आने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए ठोस नीति बनाई गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और छत्तीसगढ़ उसमें पूरे सामर्थ्य के साथ अपना योगदान दे रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख घरों तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित कर हमने 80 फीसदी लक्ष्य हासिल कर लिया है। पिछले एक वर्ष में इस अभियान ने छत्तीसगढ़ में अपनी रफ्तार पकड़ी है। हर घर को छत देने का वादा पूरा करते हुए हमने अपनी सरकार के गठन के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे 2,044 करोड़ रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित की जा चुकी है, ताकि वे अपना घर बना सकें। यह राजनीति का विषय नहीं है लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जनता के साथ छल किया था। इसके उलट एक साल के अंदर हमने सभी वर्गों का विश्वास जीता है। लोगों के चेहरों पर खुशहाली लाने में कामयाब हुए हैं।

अभी तो यह एक पड़ाव मात्र है। जैसा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास पर उद्घोष किया था कि विकसित छत्तीसगढ़ तो विकसित भारत, हमारी सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। हम सरगुजा-बस्तर की ओर देखो' की नीति पर काम कर रहे हैं। जनजातियों के कल्याण के लिए हमने आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 'नियद नेल्ला नार' योजना शुरू की है। सरकार जल्द ही चना वितरण योजना शुरू करेगी, जिससे 30 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। यह कुपोषण के खिलाफ अमोघ अस्त्र होगा। 148 हाई और हायर सेकेंडरी पीएमश्री स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब शुरू करना, आत्मसमणपत नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को 15 हजार आवास, पर्यटन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को 147.66 करोड़ की राशि की स्वीकृति, दो हजार मेगावाट की सौर परियोजना, जगदलपुर में 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण शुरू करना, सरगुजा-बस्तर के विकास पर विशेष फोकस, नई औद्योगिक विकास नीति का निर्माण, स्वास्थ्य बजट का दुगुना होना, ये सारे फैसले हमारे विजन और बुलंद इरादों को दर्शाते हैं।

25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती है जिसे हम 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाते हैं। अटल जी हमारे राज्य निर्माता है। उन्होंने इस भौगोलिक क्षेत्र को नए राज्य के रूप में आकार देकर प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया। इसी के समानांतर अपने श्रम और प्रतिभा के दम पर छत्तीसगढ़वासियों ने विकास के मामले में खुद को अन्य राज्यों से आगे लाकर खड़ा कर दिया। आंकड़े गवाही दे रहे हैं। राज्य में प्रति व्यक्ति आय 01 लाख 47 हजार 361 रुपए हो गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 7.31 प्रतिशत अधिक है। हमने विकास का ज्ञान' मडल अपनाया तथा छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी आने वाले 5 सालों में 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। हमारी नई औद्योगिक विकास नीति का उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा और 2047 के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण की परिकल्पना को साकार करना है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास हासिल करना, उनके चेहरे पर तरक्की और संतोष की मुस्कान दिखे, मेरे मुख्यमंत्री होने की सार्थकता इसी में है।

भारत-रत्न अटलजी की एक कविता की यह पंक्तियां हमें प्रेरित करती हैं कि :

जीवन को शत-शत आहुति में,
जलना होगा, गलना होगा
क़दम मिलाकर चलना होगा।

-लेखक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं।

मुद्दा

बलदेव राज भारतीय

बांग्लादेश संकट : हिन्दू आखिर किसके भरोसे

विश्व के अनेक देशों में आज युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, वैसा ही एक संकट आज बांग्लादेश में उत्पन्न हो रहा है। इस संकट का बीजारोपण आज नहीं बल्कि धर्म और जिहाद की आड़ में वर्षों पहले ही रोपित हो चुका था। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार न केवल मानवाधिकारों का हनन है बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए भी चुनौती बन गया है। बीते कुछ वर्षों में, बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतों का उभार हुआ है, और उनके हाथों में सत्ता की चाबी आने के बाद से स्थिति और भी विकट हो गई है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक लंबे समय से उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पुजारियों पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं, और हिंदू परिवारों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो लोग धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें जान से मार दिया जाता है। इन घटनाओं ने अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भय और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है कि विश्व मानवाधिकार आयोग वाले कहीं सोए पड़े हैं। उन्हें हिन्दू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार दिखाई नहीं पड़ रहे। जिन लोगों को भारत में रहने पर डर लगता था, उन्हें शायद बांग्ला देश की घटनाएं सुकून देने वाली लगती होंगी। हिंदू धर्मस्थलों पर हमले की घटनाएं बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतों की योजनाबद्ध साजिश को उजागर करती हैं। इन घटनाओं का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि सरकारी तंत्र इन पर अंकुश लगाने की बजाय इन्हें बढ़ावा दे रहा है।

मोहम्मद युनुस जैसे नेताओं के प्रभाव के तहत, पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान से हथियार खरीदे जा रहे हैं और देश में बड़े पैमाने पर सैन्य सामग्री का संग्रह हो रहा है। इस प्रकार के कदम न केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। हथियारों और सैन्य सामग्री का यह संग्रह स्पष्ट रूप से किसी बड़े उद्देश्य की ओर इशारा करता है। क्या यह भारत के खिलाफ किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या बांग्लादेश में उभरते चरमपंथी तत्व क्षेत्र में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं? ये सवाल गंभीर चिंताओं को जन्म देते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश का साझा इतिहास और भूगोल इस संकट के प्रभाव को सीमित करने की अनुमति नहीं देता। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भी लाखों लोग भारत में शरण लेने को मजबूर हुए थे। वर्तमान में भी यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई, तो भारत को एक नए शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश से पलायन कर आए शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि भारत में सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले से ही संसाधनों की कमी है। इन परिस्थितियों में, बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आगमन स्थानीय आबादी के साथ संघर्ष का कारण बन सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबी सीमा है, जो कई जगहों पर छिद्रपूर्ण है।

ऐसे में चरमपंथी तत्वों और उनके विचारों का भारत में प्रवेश करना आसान हो सकता है। यह स्थिति भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की शांति और स्थिरता को बाधित कर सकती है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। लेकिन अगर बांग्लादेश सरकार चरमपंथी ताकतों पर अंकुश लगाने में विफल रहती है, तो यह द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर कर सकता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति सुधारने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बांग्लादेश पर यह दबाव बनाना चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार संगठनों को इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो इसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर पड़ेगा। भारत सरकार को भी चाहिए कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर वह बांग्लादेश को चेतावनी दे और वहां पर हालात सही होने तक समस्त भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दे। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि उसकी आंतरिक स्थिरता और विकास तभी संभव है, जब वह सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करे। भारत को भी अपने पड़ोसी देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा।

(लेखक इतिहास प्रवक्ता एवं स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

संकलित दर्शन

हर युग में प्रासंगिक 'महादेव'

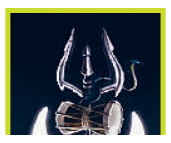

कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आदियोगी शिव का प्रशंसक हूं। प्रशंसक होने का अर्थ है कि उसकी भावनाओं से जुड़ जाना। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं शिव को महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं, क्योंकि उनका योगदान काल के परे है। इसलिए वे सदा प्रासंगिक हैं। किसी भी पीढ़ी में किसी इंसान की प्रशस्ति उस योगदान के लिए की जाती है, जो उसने उस पीढ़ी या आने वाली पीढ़ियों के लिए किया है। इस धरती पर कई ऐसे लोग आए हैं, जिन्होंने दूसरों के जीवन में योगदान

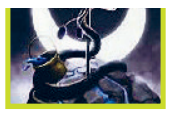

किया है। जो उस समय की जरूरत के अनुसार था, वह उस लेकर आया। गौतम बुद्ध के समय समाज कर्मकांडों में लिपटा हुआ था। जब उन्होंने बिना किसी कर्मकांड के आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू की तो वह लोकप्रिय हो गए। अगर समाज में कर्मकांड नहीं होते, तो वह इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन फिर भी, यदि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध नहीं होता, तो वह सिर्फ अपने आसपास की जगहों पर प्रभावशाली होते। आदियोगी या शिव का महत्व यही है कि उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं हुआ। उन्होंने मानव चेतना को इस प्रकार से विकसित करने के साधन और तरीके दिए कि वे हर युग में प्रासंगिक रहें। हमने उन्हें महादेव की उपाधि दी, क्योंकि उनके योगदान के पीछे की बुद्धि, दृष्टि और ज्ञान अद्भुत है।

संकलित प्रेरणा

बिना लड़ाई किए धैर्य से भी जीता जा सकता है

महाभारत में युधिष्ठिर को चक्रवती सम्राट बनाने के लिए राजसूय यज्ञ किया गया था। इसके लिए सभी राजाओं पर जीत हासिल करनी थी। इस काम के लिए अर्जुन ने विजय यात्रा शुरू कर दी। जहां-जहां अर्जुन जा रहे थे, वहां के राजाओं को पराजित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो राजा अर्जुन की सेवा स्वीकार कर रहे थे, अर्जुन उन पर कर लगाकर आगे बढ़ रहे थे। इस यात्रा के दौरान अर्जुन कुरु नाम के राज्य में पहुंचे। अर्जुन पहुंचे तो कुरु राज्य के द्वारपाल और लोगों ने अर्जुन से कहा कि आप इस नगर

का युद्ध करके जात नहा सकत, क्याक जा व्याक्त इस नगर म युद्ध क लिए प्रवश करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा इस राज्य को वरदान मिला हुआ है। अर्जुन ने सोच-विचार करके कहा कि ठीक है, मैं यहां युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन की बात सुनकर लोगों ने कहा कि युद्ध के अलावा अगर आपकी कोई इच्छा है तो वह पूरी हो सकती है। अर्जुन ने कहा कि मैं हमारे भाई युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूं। मुझे आपसे युद्ध नहीं करना है। आप बस मुझे कर के रूप में थोड़ा सा धन दे दीजिए। ये धन लेकर मैं लौट जाऊंगा। लोगों ने अर्जुन की बात मानकर थोड़ा सा धन दे दिया। धन लेकर अर्जुन दूसरे राज्य की ओर बढ़ गए। अर्जुन ने संदेश दिया है कि हर शत्रु को युद्ध करके पराजित नहीं किया जा सकता है, कुछ शत्रुओं के सामने बुद्धि और धैर्य का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि का उपयोग करते हुए भी शत्रुओं की हराया जा सकता है।

अंतर्मन

आज की पाती

पाक के पास जा रहा बांग्लादेश

1971 के मुक्ति संग्राम के बाद भारत के सैन्य समर्थन से पाकिस्तान से आजाद हुआ बांग्लादेश इन दिनों भारत से दूर और पाकिस्तान के पास जाता नजर आ रहा है। इस साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही वहां सियासी उथल-पुथल चल रही है और माहौल में भारत के खिलाफ नफरत घोलकर पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाई जा रही है। साफ लगता है कि बांग्लादेश अपने और भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधार रहा है। और संदेश देना चाहता है कि वह अब दक्षिण एशियाई राजनीति को भारत के नजरिए से नहीं देखेगा। हाल के दिनों में पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि अब बांग्लादेशी नागरिक बिना किसी वीजा शुल्क के उनके देश की यात्रा कर पाएंगे। दोनों देशों में सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की भी घोषणा की गई है। *- संकेत अग्रवाल, भाटापारा*

ट्रेंड

संविधान का अपमान शर्मनाक

महाराष्ट्र के परभणी मेंभारतरत्न बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा एवं संविधान का किया गया अपमान अति-निन्दनीय व शर्मनाक। वहाँ की सरकार, ऐसे जातिवादी व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तुरन्त सख्त कानूनी कार्रवाई करे।

-मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

दलितों पर अत्याचार

आज हाथरस जाकर 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बातें बताईं उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। इस परिवार की हताशा और निराशा भाजपा द्वारा दलितों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार की सच्चाई को दिखाते हैं।

- राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

कानून का शासन लाएंगे

क्रिस्टोफर रे का इस्तीफा अमेरिका के लिए एक महान दिन है क्योंकि यह अन्याय विभाग के रूप में जाने जाने वाले हथियारीकरण को समाप्त कर देगा। अब हम सभी अमेरिकियों के लिए कानून का शासन बहाल करेंगे।

-डोनाल्ड ट्रम्प, राष्ट्रपति, यूएसए

एआई कार्यक्रम

आशा भय, विश्वास, प्रेम, अनिश्चितता और अक्सर मूर्खता का मिश्रण है .. मुझे संदेह है कि कोई भी इन भावनाओं को एआई कार्यक्रम में कोड कर सकता है। इससे डरने का एकमात्र कारण हमारी अपनी जड़ता है। **-शेखर कपूर, फिल्मकार**

करंट अफेयर

हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए सांसद दोषी

हांगकांग के एक न्यायाधीश ने लोकतंत्र समर्थक एक पूर्व सांसद को जुलाई 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान शहर में एक मेट्रो स्टेशन पर भीड़ द्वारा हिंसा के दौरान दंगा करने के लिए बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया। अभियोजकों ने लैम चेउक-टिंग पर लकड़ी के डंडों और धातु की छड़ लिये लगभग 100 लोगों के एक समूह को उकसाने का आरोप लगाया। अभियोजकों के मुताबिक, इन लोगों ने ट्रेन स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों और राहगीरों पर हमला किया। अभियोजकों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने काली शर्ट पहनी थी जबकि कुछ लोगों ने सफेद शर्ट पहनी हुई थी और वे दावा कर रहे थे कि वे हांगकांग के नये क्षेत्रों के एक आवासीय जिले यूएन लॉन्ग में अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। हिंसा में लैम समेत दर्जनों लोग घायल हो गये थे और इस हिंसा ने विरोध आंदोलन को और तेज कर दिया क्योंकि जनता ने पुलिस की देरी से की गई कार्रवाई की आलोचना की थी। न्यायाधीश स्टेनली चेन ने फैसला सुनाया कि लैम मध्यस्थ के रूप में काम नहीं कर रहा था जैसा कि उसने दावा किया था बल्कि वह राजनीतिक लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि लैम के शब्दों ने सफेद शर्ट पहने लोगों को उकसा दिया।

ऑफ बीट

मोटापा लोगों को गहराई तक प्रभावित करता है

ज्यादा वजन वाले लोग एक ऐसे कलंक में जी रहे होते हैं, जो व्यापक है और इन लोगों को कहीं गहराई तक प्रभावित करता है। इसे भेदभाव के अंतिम स्वीकार्य रूपों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ शोधकर्ता सोचते हैं कि 'मोटापा' शब्द ही समस्या का हिस्सा है, और कलंक को कम करने के लिए नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका सुझाव है कि इसका नाम 'वसा-आधारित पुरानी बीमारी' रख दिया जाए। बड़े शरीर में रहने वाले 42 प्रतिशत वयस्कों को अपने वजन को लेकर शर्मिंदगी का अनुभव होता है। ऐसा तब होता है जब दूसरों की उनके प्रति नकारात्मक मान्यताएं, दृष्टिकोण, धारणाएं और निर्णय होते हैं, उन्हें गलत तरीके से आलसी समझा जाता है और यह माना जाता है कि उनमें इच्छाशक्ति या आत्म-अनुशासन की कमी होती है। बड़े शरीर वाले लोग कार्यस्थल, अंतरंग और पारिवारिक संबंधों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मीडिया सहित कई क्षेत्रों में भेदभाव का अनुभव करते हैं। वजन को लेकर शर्मिंदगी महसूस करना बढ़े हुए कोर्टिसोल स्तर (शरीर में मुख्य तनाव हार्मोन), शरीर की नकारात्मक छवि और खराब मानसिक स्वास्थ्य सहित कई नुकसान से जुड़ा हुआ है।

किसान व आम जनता से वादा खिलाफी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर कुसमी में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

कुसमी,14 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को एक साल पूरा हो गया है. भाजपा सरकार की नाकामियों को जानता के बिच रखकर कुसमी नगर के बस स्टेण्ड के समीप में कांग्रेस नेताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन कर जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रदेश सरकार पर किसानों व आम जनता से वादा खिलाफी करने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी की गई।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुसमी अध्यक्ष सह जनपद पंचायत कुसमी के उपाध्यक्ष हरीश मिश्रा ने बताया की भाजपा के एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित विभिन्न जनहित के मुद्दे से आम जनता बदहाल हो गई है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में भाजपा सरकार की एक वर्ष के असफल कार्यकाल में बेहाल हुई छत्तीसगढ़ की स्थिति को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से धरना प्रदर्शन आयोजित किया है।

धरना प्रदर्शन में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आयोजित सभा पर कहा कि

भाजपा के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। लगातार प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती , चाकू बाजी जैसे कई गंभीर अपराध हो रहे हैं, जिसे रोकने में भाजपा की सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। इसके साथ ही समर्थन मूल्य में हो रही धान खरीदी में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा सरकार ने किसानों को 3100 रुपये देने का घोषणा किया था, लेकिन किसानों को सिर्फ समर्थन मूल्य की राशि 2300 रुपये ही मिल रही है।इसके साथ ही किसानों को टोकन, बारदाना जैसे कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भगत, जनपद सदस्य देवधान भगत, पूर्व मंडी अध्यक्ष बालेश्वर राम, पार्षद ललित निकुंज, पार्षद पति पंकज दुबे, मुजस्सम अली, सोनू अली, विक्रम गुप्ता, फरीद खान सहित कई कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे। आयोजित सभा में मंच का संचालन युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दीपक बुनकर ने किया तथा आभार व्यक्त विधानसभा उपाध्यक्ष मुदस्सीर इराकी ने की।

नपं चुनाव में कांग्रेस को बहुमत दिलाने जानता से अपील

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरीश मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र भगत ने आयोजित सभा के बिच जनता से अपील करते हुवें कहा हैं की आगामी नगर पंचायत का चुनाव होने वाला हैं आप सभी कांग्रेस के नीतियों को समझें तथा कांग्रेस को बहुमत देकर विजयी बनाये।

जैसा मैंने यूजिन पटेल को देखा

निर्मल तिग्गा
सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर

28 मार्च 1926 को गाब्रिएल मुंशी और मोनिका के घर पहलौटे के रूप में यूजिन तिग्गा का जन्म हुआ और यही आगे चलकर मेरे पिताश्री हुए। दुनिया में कितनी शख्सियत आती हैं और गुमनामी के अंधेरे में विलीन हो जाती है। बहुत कम personality ऐसे होते हैं जो unsung heroबन पाते हैं।ऐसी विभूतियां कम होती हैं जिन्हें इतिहास याद रखता है। यूजिन तिग्गा को भी इसी सामान्य श्रेणी में ही गिना जा सकता है। किसी अपने निकटवर्ती जन खासकर पिता के संबंध में कुछ कहना या बताना कम खतरे का काम नहीं है। इसमें पक्षपात का बड़ा जोखिम है। जो भी हो मैंने आज यह दुःसाहस तो कर ही दिया है और इसके लिये कलम पर छोड़ दिया है, जो बताना चाहे बताये, जो लिखना चाहे लिखे।सब यश-अपयश उसके सर !

हाँ, तो मैं कह रहा था... उन दिनों गाब्रिएल गिनाबहार मिशन संस्था में मुंशी का काम करते थे अतः उनका परिवार वहीं बसता था। यूजिन की पढ़ाई- लिखाई प्राइमरी से सातवीं मिडिल तक गिनाबहार में हुई। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान प्राप्त हुआ। मिडिल पास करने के कुछ समय बाद, एक दिन ऑफिस से लौटकर गाब्रिएल ने पत्नी मोनिका को किशोर यूजिन के बारे में अपना निर्णय सुनाया। सुनकर मोनिका का कोमल मातृहृदय द्रवित हो गया।

महासभा जिला सरगुजा द्वारा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन ...!

प्रदेश आवाहन पर ओबीसी महासभा के पदाधिकारी ने कलेक्टर से मुलाकात की।

कई मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन...

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सरगुजा - ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया जाना तय किया गया था। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष व सरगुजा संभाग के प्रभारी परशुराम सोनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिध मंडल सुभाष साहू प्रदेश सचिव ओबीसी महासभा, आदित्य गुप्ता जिला कार्य समिति सदस्य प्रमुख रूप से

उपस्थित रहे साथ ही सत्यनारायण वर्मा , कृष्णा सोनी, राम अवतार गुप्ता, रघुनंदन, युगल किशोर, विकास ठाकुर, राजेश इनके अलावा ओबीसी महासभा के कई पदाधिकारी एवं सम्माननीय सदस्य गण उपस्थित रहे। ज्ञापन देते हुए ओबीसी महासभा के पदाधिकारी ने बताया कि अधिकांश संभाग व जिलों में ओबीसी की जनसंख्या 27 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद भी उन्हें जनसंख्या के अनुपात में न देकर अधिकतम 27 प्रतिशत आरक्षण का सीमित प्रावधान किया गया है। जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय व असंवैधानिक है। तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल जैसे राज्यों में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में 50, 49 और 40 प्रतिशत तक आरक्षण लागू है। छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण जो राज्यपाल महोदय के पास लंबित है उसको अभिलंब पास कर पिछड़ा वर्ग के हित में कार्य करने की बात कही गई। अवगत हो कि अधिकांश संभाग, जिलों में ओबीसी की जनसंख्या 27% से अधिक होने के बावजूद भी उन्हें जनसंख्या के अनुपात में न देकर अधिकतम 27% प्रतिनिधित्व का सीमित प्रावधान किया गया है। जो कि प्रदेश के अर्थव्यवस्था में रीड की हड्डी बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय के साथ घोर अन्याय एवं असंवैधानिक है। अवगत हो कि तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल जैसे राज्यों में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में क्रमश 50, 49 और 40% प्रतिनिधित्व आरक्षण लागू है अतः इन राज्यों की भांति 42% प्रतिनिधित्व आरक्षण लागू किए जाने का निवेदन किया गया है। अतः राज्य सरकार को उक्त तथ्यों एवं ऊपर उल्लेखित तीनों राज्यों के आरक्षण व्यवस्था के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्व कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया गया है ।

पेट्रोल टैंकर और पिकअप में आमने-सामने भिड़ंत, चालक की मौत

दो गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

तारा - कोरबा जिले के मोरगा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एनएच-130 के पुटा घाट पर मंगलवार सुबह करीब 7 बजे पेट्रोल टैंकर और पिकअप वाहन की आमने-सामने भीषण भिड़ंत में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में पिकअप सवार पांच अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की स्थिति गंभीर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिकअप वाहन (क्र. यूपी-61बीटी-4748) सासाराम, बिहार से महाराष्ट्र चप्पल बेचने जा रहा था। वहीं पेट्रोल लोड टैंकर (क्र. सीजी-15एसी-0743) बिलासपुर से अंबिकापुर की ओर जा रहा था। पुटा घाट पर दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हुई, जिससे पिकअप चालक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना में पिकअप सवार पारस चौहान, सुग्रीव कुमार राय, अखिलेश चौहान, कमलेश चौधरी और उमापति चौहान घायल हुए हैं। इनमें से दो की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। टैंकर चालक को भी चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मोरगा चौकी प्रभारी मंतू राम मरकाम, आरक्षक देवेन्द्र पैकरा, महिपाल सिंह और सरजीत सिंह ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। सभी घायलों को उदयपुर से आई एंबुलेंस द्वारा सीएचसी उदयपुर ले जाया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मृतक के परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है।

नई औद्योगिक नीति से भारत का इंडस्ट्रीयल हब बनेगा छत्तीसगढ़ : विष्णुदेव साय

भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकॉनोमिक कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने साझा किए विचार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर । नई औद्योगिक नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ को भारत का इंडस्ट्रीयल हब बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। इस नीति के तहत क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर जोर

दिया गया है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकॉनोमिक कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ऑनलाइन जुड़ कर यह बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ में पांच लाख नौकरियां सृजित की जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन सहित कई अन्य सहायता दी जा रही है, जिसके तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर उद्योगों को उनके वेतन का 40 प्रतिशत तक सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस नीति के तहत बस्तर में उद्योग लगाने पर स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के तहत उद्योगों को 45% तक की सहायता दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ शासन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर केंद्रीय जेल में संगोष्ठी का हुआ आयोजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर / छत्तीसगढ़ शासन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर सुशासन का एक साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में शनिवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक ह्लएक प्रयास स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता की ओरह्व रहा। इस अवसर पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं आरसेटी अधिकारी अम्बिकापुर श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री विरेन्द्र अम्बष्ट, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरसेटी मास्टर ट्रेनर कुमारी तमन्ना निशा उपस्थित रहे। मास्टर ट्रेनर द्वारा जेल में निरूद्ध बंदियों को दिये जाने वाले बैंक ऋण से संबंधित विस्तृत जानकारी

जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, अटल पेंशन योजना, खादी ग्रामोद्योग योजना आदि योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। जेल अधीक्षक श्री योगेश सिंह क्षत्री द्वारा बताया गया कि इस जानकारी से लाभ प्राप्त कर बंदीगण रिहाई पश्चात अपनी आजीविका व जीवकोपार्जन को प्राप्त करने में सहायक होंगे और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर समाज में पुनः स्थापित होकर अपनी नैतिक भूमिका निभा सकेंगे। कार्यक्रम में उप जेल अधीक्षक श्री आर.आर. मातलाम, सहायक जेल अधीक्षक श्री ए.के. बाजपेयी, सहायक जेल अधीक्षक श्री संजय कुमार खैरवार सहित समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०/31-2/2024-25

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नेहाल अख्तर पिता अफजल हुसैन जाति मुसलमान निवासी मनेन्द्रगढ़.तहसील मनेन्द्रगढ़ जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम श्रीगढ़ तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 102/7 रकबा 0.010 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 29/12/2024 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 13/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०./अ-2/2024-25

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कमल अख्तर पिता अफजल हुसैन जाति मुसलमान निवासी मनेन्द्रगढ़.तहसील मनेन्द्रगढ़.जिला कोरिया (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम श्रीगढ़.तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 101/4 रकबा 0.010 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 29/12/2024 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 13/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०/अ-2/2024-25

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मो० आरिफ आ० मो० मोईन जाति मुसलमान निवासी नवागढ़ तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम कांतिप्रकाशपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 393/13 रकबा 0.012 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 29/12/2024 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 13/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र० क्र०/अ-2/2024-25

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मुशर्रत खातुन पत्नी मो० ताहिर खान जाति मोमिन निवासी नवागढ़ तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम कांतिप्रकाशपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (४०ग०) खसरा नंबर 393/11 रकबा 0.032 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 29/12/2024 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वय अधवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 13/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०-/अ-6/2024-25

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक नीलचन्द्र सिंह आ. स्व. रामशंकर सिंह, निवासी गुदरी चौक (डी०सी० रोड़) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक के के पिता स्व. रामशंकर सिंह आ. रामलखन सिंह के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, मोहल्ला डी०सी० रोड़, स्थित शीट नं. 03 की नजूल भूमि खसरा क्रमांक 1374/3 रकबा 0.12 1/2 एकड़ भूमि है। भू-धारक रामशंकर सिंह की मृत्यु दिनांक 08/04/2021 को हो गई है। उक्त भूखण्ड को भूधारक रामशंकर सिंह द्वारा वसीयतनामा दिनांक 12.03.2020 के माध्यम से आवेदक को प्रदान कर दिया गया है। अतः उक्त वसीयतनामा दिनांक 12.03.2020 के आधार पर आवेदक द्वारा उक्त भूमि के नजूल अभिलेख में स्वयं का नाम नामांतरण कराने हेतु वसीयतनामा दिनांक 12.03.2020 की छायाप्रति, मयदस्तावेज सहित आवेदन पत्र, अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 27/12/2024 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक- 13/12/2024 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

स्वयंसेवी शिक्षकों को साक्षरता केंद्र संचालन के लिए प्रोत्साहित करें

उल्लास नवभारत साक्षरता की दिलाई गई शपथ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर - राज्य साक्षरता प्राधिकरण मिशन एवं राज्य साक्षरता केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित कलेक्टर एस जयवर्धन के निर्देशन तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडित भारद्वाज एवं बीपीओ रविनाथ तिवारी के मार्गदर्शन में शासकीय माध्यमिक विद्यालय पतरापाली में संकुल स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। उक्त बैठक संकुल के समस्त विद्यालय के शिक्षक उपस्थित थे उनके मध्य उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए बीपीओ रविनाथ तिवारी ने बताया कि अपने विकासखंड के समस्त ग्राम पंचायत में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप सभी अपने अपने ग्राम पंचायत में नवभारत साक्षरता का प्रचार प्रसार करते हुए साक्षरता केंद्रों में असाक्षरों की सत प्रतिशत उपस्थिति बढ़ाएं, उल्लास पुस्तिका का नियमित पाठन वित्तीय साक्षरता, चुनावी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, विधिक साक्षरता, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, स्वच्छता पर जागरूकता के संबंध में नवसाक्षरों को जानकारी देने तथा स्वयं सेवीशिक्षकों को साक्षरता केंद्र संचालन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिए, वही स्कूल में उपस्थित सभी बच्चों को उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का शपथ दिलाया गया। इस दौरान संकुल प्राचार्य हेमसाय सिंह, संकुल समन्वयक जी डी सिंह, संतोष जायसवाल, योगेश साहू, अनिता सिंह, कृष्णकुमार यादव, उर्मिला सिंह, प्रवीना, रघुनाथ जायसवाल, रामधन साहू, नंदकुमार सिंह, धीरेंद्र सिंह, सुखलाल सिंह, सुमेर साय, अजय साहू, अल्का कुजूर सहित संकुल के शिक्षक, शिक्षिकाए एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

बस्तर ओलंपिक 2024
करसाय ता बस्तर बरसाय ता बस्तर
बस्तर ओलंपिक 2024
सुशासन का 1 साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल
खेलों के जरिए सुखद भविष्य की ओर बढ़ता बस्तर
श्री अमित शाह
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर
हमने बनाया है हम ही सँवारेंगे
हमसे जुड़ने के लिए
Q.R.स्कैन करें
ChhattisgarhCMO
Visit us : DPRChhattisgarh
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ संवाद-42449/14

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के एक वर्ष की उपलब्धियों को मंत्री लक्ष्मी ने किया साझा

0 बोली-सेवा ही सर्वोपरि'' छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र 0 कलेक्ट्रेट सभागार में हुई मंत्री लक्ष्मी की पत्रकार वार्ता

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के एक वर्ष का पूरा होने पर शनिवार को यहां जिला कार्यालय में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रेसवार्ता कर सरकार के विभिन्न योजनाओं की सिलसिरेवार उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा 'सेवा ही सर्वोपरि'' छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र है जिसका अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को साझा किया और बताया कि कैसे एक साल में राज्य ने विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन की स्थापना के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया और प्रशासनिक सुधारों के जरिए जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने की दिशा में काम किया। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा, बाबूलाल अग्रवाल, मुरली मनोहर सोनी, शशिकान्त गर्ग, संदीप अग्रवाल, बसन्त कुशवाहा, राजेश्वर तिवारी, अरविन्द मिश्रा, शिव शंकर साहू, कलेक्टर एस जयवर्धन, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री ने बताया कि 13 दिसम्बर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो गया है। हमारा यह पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। बीते 12 महीनों में मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास के अनेक नये आयाम स्थापित किए हैं। इनमें से कुछ आप लोगों के साथ साझा कर रही हूं। इस एक साल में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया और उपलब्धियां हासिल की, हमारी प्राथमिकता में वे लोग रहे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के नागरिकों से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हम प्रदेश में सुशासन की स्थापना करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह तत्परता के साथ कार्यवाही की। जो लोग भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सुशासन की स्थापना के लिए हम तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण नाम से नया विभाग बनाया है। हमारा प्रयास है कि आम नागरिकों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। एक क्लिक में अथवा एक फोन कॉल में उनके काम हो जाने चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लोगों को जो गारंटियां दी थी, उनमें से अधिकांश गारंटियों को सरकार ने एक वर्ष की अल्प अवधि में ही पूरा कर दिया है।

पूरी की मोदी की गारंटियां

मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 3100

रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की रिकॉर्ड खरीदी की। हमारी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसान भाई-बहनों को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किया। प्रदेश की माताओं-बहनों से किए गए वादे को पूरा करते हुए तीन माह के भीतर ही महतारी वंदन योजना शुरू की गई। इसका लाभ 70 लाख माताओं-बहनों को मिल रहा है। अब तक इस योजना की 10 किश्तों में 6530 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। इस निर्णय पर तेजी से अमल करते हुए आवासों के निर्माण के लिए बड़ी राशि भी जारी की गई। हमारी सरकार ने प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करने के साथ-साथ पांच साल के एरियर्स का भुगतान भी किया। इस तरह हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है।

अंत्योदय के लक्ष्य की ओर

मंत्री ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संदेश के अनुरूप हमारी सरकार ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। राज्य के जनजातीय समाज के गौरव को फिर से ऊंचाई पर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। उनकी आय और रोजगार में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए। तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5.5 हजार मानक बोरा कर दी गई। जनजातीय क्षेत्रों में सड़क व अन्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अम्बिकापुर के हवाई अड्डे से भी अब हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए गठित प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया है।

जनजातीय समाज का बढ़ा गौरव

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्य के बैगा, गुनिया, सिरहा को सालाना पांच-पांच हजार रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। जनजातीय गांवों में अखरा निर्माण विकास योजना शुरू की गई है। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा नायकों की स्थान-स्थान पर प्रतिमाएं लगाने का निर्णय भी लिया गया है।

बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है कि कांगेर घाटी के गांव धुड़मारास ने अब विश्व पर्यटन के नक्शे पर जगह बना ली है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव में पर्यटन के विकास के लिए इसे दुनिया के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के गठन से भी राज्य में पर्यटन के विकास की संभावनाओं को बल मिला है। राज्य में पांच शक्तिपीठों का विकास किया जा रहा है। इसके लिए चार धाम की तर्ज पर एक हजार किलोमीटर की परियोजना शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ के साथ भगवान राम का गहरा नाता है। वे हमारे भांजे हैं। उन्होंने वनवास के 14 सालों में से 10 साल यहीं गुजारे। हमारी सरकार की कोशिश है कि दुनिया भगवान श्रीराम से हमारे इस रिश्ते को जानें। प्रदेश में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करके हमने यहां के श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम की नि:शुल्क यात्रा की व्यवस्था की, ताकि भगवान राम से अपने रिश्ते को और सघन कर सकें। हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू कर रहे हैं। हमने राजिम कुंभ कल्प का वैभव फिर से लौटाया है। नई उद्योग नीति से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। हमने इस नीति को रोजगार परक बनाया है। नई उद्योग नीति में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसमें पर्यटन को भी उद्योग के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को भी रियायत देने का विशेष प्रावधान है। राज्य में एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए एमएसएमई मंत्रालय बनाने की घोषणा कर दी गई है। नयी उद्योग नीति में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित, आत्म- समर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है।

वादा निभाया

हमने वादा किया था कि हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। इसके लिए तकनीक का प्रयोग करते हुए शासन-प्रशासन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में हमें अच्छी कामयाबी मिली है। भ्रष्टाचार के मामले में हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन के सपने को हम लगातार साकार कर रहे हैं। राज्य में गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की रियल टाइम मॉनिटरिंग अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। सीएमओ पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और उपलब्धियों की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकता है। नागरिकगण मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों से सहजता से मुलाकात कर सकें इसके लिए मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल और घर बैठे रजिस्ट्री के लिए सुगम एप शुरू किया गया है। राज्य के कार्यालयों में कामकाज में तेजी और सटीकता लाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की गई है। खनिजों के ऑनलाइन ट्रांजिट पास की व्यवस्था की गई है। जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय खरीदी और सेवाएं प्राप्त करने को अनिवार्य किया गया है। पुराणों में जिसे राम-राज कहा गया है, उसे ही हम सुशासन कहते हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान प्रदेश में नक्सलवाद का तेजी से उन्मूलन किया गया है। सरकार ने दो साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया करने का संकल्प लिया है। बीते एक वर्ष में 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। करीब 1750 नक्सलियों को या तो आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया है, या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हुए। हमने नक्सल क्षेत्रों में बंद पड़े स्कूलों को फिर से शुरू कराया है। बस्तर में बस्तर ओलंपिक का आयोजन करके हमने वहां के युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा है। माओवादी आतंक पीड़ित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण तथा शेष जिलों के विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने का निर्णय लिया गया है।

शिक्षा की नयी अलख जगाई

राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा को रोजगार परक बनाया है। राज्य की प्रतिभाओं को निखारने के लिए रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश की 13 नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरियों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। अपने वादे के मुताबिक हमने सीजीपीएससी परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हुई और उनके परिणाम घोषित हुए। इससे राज्य की प्रतिभाओं का विश्वास सीजी पीएससी पर लौट आया है। नवा रायपुर को हम आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमी कॉरिडोर का निर्माण तेजी से हो रहा है। इससे नवा रायपुर और भी तेजी से विकसित होगा। सिम्स बिलासपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से भवन विस्तार का कार्य किया गया है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया। जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ और गीदम मेडिकल कॉलेजों की निर्माण के लिए 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

केंद्र का साथ, सहयोग और मार्गदर्शन बनी ताकत

प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से एक साल में राज्य ने बहुत तेजी से प्रगति की है। केन्द्र से हमें भरपूर सहयोग और समर्थन मिला है। इस दौरान 31 हजार करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत की गई है। दो सालों में छत्तीसगढ़ में सड़कों का मजबूत नेटवर्क होगा। साथ ही रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हमें केन्द्र से अनेक महत्वपूर्ण रेल लाइनों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। हमने इस खास वर्ष में खास उपलब्धियां हासिल करने के लिए खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 नवंबर 2025 को जब हम प्रदेश स्थापना की रजत जयंती मनाएंगे।वर्ष 2028 तक प्रदेश की जीएसडीपी को दस लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हमारे विकास और विश्वास की इस यात्रा में आप हमेशा साक्षी और सहभागी रहे हैं। शासन के विकास कार्यों और लोक हितकारी योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने आप सबका सहयोग महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मैं आप सबको भी धन्यवाद देती हूं। प्रदेश की जनता का उनके समर्थन और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करती हूं। हम सभी छत्तीसगढ़ को विकसित बना कर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में अपना अमूल्य योगदान देंगे।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, पीटीएस, मैनपाट, जिला सरगुजा (छ.ग.)

हाऊसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य हेतु निविदा/भावपत्र आमंत्रण सूचना

(निविदा दिनांक 01.01.2026 से 31.12.2025 तक के लिए)

निविदा विज्ञप्ति क्र. : पुअ/पीटीएस/मैनपाट/फड/03/2024
दिनांक 10 12.2024

पीटीएस मैनपाट, जिला सरगुजा के प्रशासनिक भवन, गेस्ट हाऊस, एनजीओ हॉस्टल बैरक, नव आरक्षक बैरक, डायनिंग हॉल, पुरुष टॉयलेट-बाथरूम और परिसर अंदर की हाऊसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य हेतु वार्षिक अनुबंध पर ठेका दिये जाने हेतु दिनांक 24.12.2024 के 15:00 बजे अपरान्ह तक सीलबंध लिफाफे/भावपत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऐसी इच्छुक संस्था/फर्म जिन्हें किसी शासकीय/ अर्धशासकीय/निगमित निकायों/ सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो वे निर्धारित निविदा प्रपत्र, नियम एवं शर्ते इस कार्यालय से प्राप्त कर, निर्धारित धरोहर राशि के साथ आवेदन कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र आवेदन पत्र के साथ रूपये 500.00 (पांच सौ मात्र) का चालान कोषालय में लेखा शीर्ष 0055 पुलिस शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियां मद में जमा कर चालान की मूल प्रति पीटीएस मैनपाट कार्यालय में प्रस्तुत कर दिनांक 20.12.2024 के 15:00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

01. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि – 20.12.2024 के 15:00 बजे तक।
02. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 24.12.2024 के 15:00 बजे तक।
03. निविदा खोलने की तिथि – 26.12.2024 के 12:30 बजे ।

(नोट :– निविदा प्रपत्र विक्रय स्थल– पीटीएस मैनपाट, जिला सरगुजा (छ.ग.)

पुलिस अधीक्षक
पीटीएस, मैनपाट
जिला सरगुजा

जी-242504509/5

जनसंपर्क विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां जिला संयुक्त कार्यालय प्रागंण में सुशासन का एक साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल पर आधारित जिले के विकासमूलक फ़ोटो प्रदर्शनी का अवलोकन जिले के नागरिकों द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन के एक वर्ष पूरा होने पर जिला कार्यालय परिसर में ''सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल'' के थीम में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने जनसंपर्क विभाग द्वारा फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। फोटो प्रदर्शनी का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना है। इसमें विभिन्न शासकीय योजनाओं की लाभ और उनके क्रियान्वयन की तस्वीरों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही जिला कार्यालय में आने वाले नागरिकों को योजनाओं से संबंधित पत्रिकाओं और जन मन का वितरण भी किया गया।

उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम पर पतरापाली स्कूल में दिलाई गई शपथ

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। राज्य साक्षरता प्राधिकरण मिशन एवं राज्य साक्षरता केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशन तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडित भारद्वाज एवं बीपीओ रविनाथ तिवारी के मार्गदर्शन में शासकीय माध्यमिक विद्यालय पतरापाली में संकुल स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। उक्त बैठक संकुल के समस्त विद्यालय के शिक्षक उपस्थित थे, उनके मध्य उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए बीपीओ रविनाथ तिवारी ने बताया कि अपने विकासखंड के समस्त ग्राम पंचायत में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप सभी अपने अपने ग्राम पंचायत में नवभारत साक्षरता का प्रचार प्रसार करते हुए साक्षरता केंद्रों में असाक्षरों की शत प्रतिशत उपस्थिति बढ़ाएं, उल्लास पुस्तिका का नियमित पाठन वित्तीय साक्षरता, चुनावी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, विधिक साक्षरता, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, स्वच्छता पर जागरूकता के संबंध में नवसाक्षरों को जानकारी देने तथा स्वयं सेवीशिक्षकों को साक्षरता केंद्र संचालन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिए। वही स्कूल में उपस्थित सभी बच्चों को उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का शपथ दिलाया गया। इस दौरान संकुल प्राचार्य हेमसाय सिंह, संकुल समन्वयक जी.डी. सिंह, संतोष जायसवाल, योगेश साहू, अनिता सिंह, कृष्ण कुमार यादव, उर्मिला सिंह, प्रवीना, रघुनाथ जायसवाल, रामधन साहू, नंदकुमार सिंह, धीरेंद्र सिंह, सुखलाल सिंह, सुमेर साय, अजय साहू, अलका कुजूर सहित संकुल के शिक्षक, शिक्षिकाए एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.1, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
eProcurement Portal: https://eproc-cgstate-gov-in
(प्रथम आमंत्रण)

निविदा सूचना क्रमांक : 05/व.ले.लि./2024–25, दिनांक 06.12.2024 निम्नलिखित कार्यों के लिये दिनांक 27.12.2024 (17.30 बजे) तक ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :–

ग्रुप क्र.	सिस्टम निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत
1	162361	बटवाही करीलधोवा नाला में एनीकट सह पुलिया निर्माण कार्य।	रू. 245.94 लाख।
2	162362	लमगांव स्टापडेम कम काजवे निर्माण कार्य।	रू. 246.94 लाख।
3	162363	केराकछार एनीकट योजना का निर्माण कार्य।	रू. 247.84 लाख।
4	162366	रजपुरी स्टापडेम योजना का निर्माण कार्य।	रू. 251.17 लाख।
5	162367	पैगा स्टापडेम योजना का निर्माण कार्य।	रू. 253.53 लाख।
6	162368	बमलाया झींगानाला एनीकट योजना का निर्माण कार्य।	रू. 261.55 लाख।

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई–प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 13.12.2024, समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते है। नोट : निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई–प्रोक्योरमैट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र. 1,
अम्बिकापुर (छ.ग.)
कृते – मुख्य अभियंता
हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग
अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

जी–242504563 / 1

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड- बलरामपुर (छ.ग.)
E-mail: echalram-phe-cg@nic.in

रूची की अभिव्यकित क्र. /03/ले.शा/ज.जी.मि/का.अ./लो.स्वा.यां.वि./2024
बलरामपुर, दिनांक 11.12.2024

ऑनलाईन द्वितीय निविदा आमंत्रण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से जल जीवन मिशन अंतर्गत आई.एस.ए. के लिए निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है –

सि. नि. क्र.	आई.एस.ए. का कार्य (रू.करोड़ में)
162754	2.46

निविदा एवं कार्य का विस्तृत विवरण यथा धरोहर राशि, बिड वैद्यता की तिथि, कार्य की अवधि, निविदाकार की श्रेणी, एवं कार्यों तथा स्थल संबंधी जानकारी ऑन लाईन ई–प्रोक्युरमेंट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 17.12.2024 से देखी जा सकती है तथा निविदा दिनांक 07.01.2024 तक बिड डाली जा सकती है। निविदा में आगामी संशोधन पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किए जावेगे। अतः निविदाकार ऑन लाईन निविदा प्रक्रिया में सतत् संपर्क में रहें। अन्य विवरण कार्यालयीन समय पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड बलरामपुर में देखे जा सकते हैं।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड–बलरामपुर (छ.ग.)

जी–242504543 / 10

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड- बलरामपुर (छ.ग.)
E-mail: echalram-phe-cg@nic.in

रूची की अभिव्यकित क्र. /04/ले.शा/ज.जी.मि/का.अ./लो.स्वा.यां.वि./2024
बलरामपुर, दिनांक 12.12.2024

ऑनलाईन निविदा आमंत्रण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से जल जीवन मिशन अंतर्गत Kala Jaththa/Kala Mandli/ Nacha dal के विभिन्न कार्यों के लिए रूची की अभिव्यक्ति हेतु निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है –

सि. नि. क्र.	कार्य की अनुमानित लागत (रू.लाख में)
162793	31.48

निविदा एवं कार्य का विस्तृत विवरण यथा धरोहर राशि, बिड वैद्यता की तिथि, कार्य की अवधि, निविदाकार की श्रेणी, एवं कार्यों तथा स्थल संबंधी जानकारी ऑन लाईन ई–प्रोक्युरमेंट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 19.12.2024 से देखी जा सकती है तथा निविदा दिनांक 08.01.2024 तक बिड डाली जा सकती है। निविदा में आगामी संशोधन पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किए जावेगे। अतः निविदाकार ऑन लाईन निविदा प्रक्रिया में सतत् संपर्क में रहें। अन्य विवरण कार्यालयीन समय पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड बलरामपुर में देखे जा सकते हैं।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड–बलरामपुर (छ.ग.)

जी–242504566 / 2

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 9713108088
8719000259

कोरिया फ्रंटलाइन

विवेकानंद महाविद्यालय में नि:शुल्क स्वैच्छिक रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

छ.ग. फ्रंटलाइन मनेन्द्रगढ़ (एमसीबी) । शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ में नि:शुल्क रक्तदान शिविर एवं रक्तदान जागरूकता व्याख्याता का आयोजन केन्द्रीय चिकित्सालय मनेन्द्रगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार के नेतृत्व में डॉ. लवलेश गुप्ता, डॉ. एस.एस. नायक, विंसी सिंह, रूपेन्द्र सिहं, कृष्णा राम के सौजन्य से आयोजित हुआ जिसमें राजसिंह, सुमित कुमार, परमेश्वर,मीना कुमारी, उमेश कुमार, अमन जयसवाल, बाल कृष्ण,संध्या गुप्ता, रामनिवास गुप्ता, महफुस अलम, निर्मला, ई अनुषका, समिला मिंज, हेमन्त सिंह, रागिनी यादव, कमलेश पटेल (सहा.प्राध्यापक) सहित अनेक युवाओं ने रक्तदान किया रक्त दान के पूर्व जागरूकता उद्बोधन देते हुए डॉ. लवलेश गुप्ता द्वारा रक्तदान के महत्व एवं आवश्यकता के बारे में प्रकाश डालते हुए रक्त दान करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्सहित किया। निर्भय अक्षय भारत निर्माण निमित नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं जागरूकता अभियान का आयोजन डॉ. अविनाश खरे जिला चिकित्सा अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के सौजन्य से किया गया । जिसमें 50 छात्र-छात्राओं का सिकल सेल परीक्षण भी किया गया परीक्षण का परिणाम सकरात्मक रहा महाविद्यालय में किये गये परीक्षण में सभी परिणाम निगेटिव रहा स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त जारूरत मंद छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क दवाई वितरित की गई रक्त दान शिविर एवं निर्भय अक्षय भारत निर्माण निमित छात्रा-छात्राओं को क्षय रोग के कारण लक्षण, एवं बचाव की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संयोजन शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रेडक्रॉस, समिति रेडरिबन

क्लब, गृहविज्ञान विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना महिला एवं पुरूष इकाई के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन प्राचार्य डॉ.श्राबनी चक्रवर्ती द्वारा दिया गया ।कार्यक्रम का संयोजन डॉ. सरोजबाला श्याग विश्नोई, श्रीमती अनुपा तिग्गा, रंजीतमणी सतनामी द्वारा किया गया था। सभी रक्त दाताओं को केन्द्रीय चिकित्सालय मनेन्द्रगढ़ के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया कार्यक्रम के अन्त में डॉ. विश्नोई द्वारा केन्द्रीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं पूरी टीम के प्रति तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला-एमसीबी. डॉ. अविनाश खरे ,नोडल एमसीबी. जिला शाखा भारतीय रेडक्रास सोसायटी, सोमेन्द्र मंडल के प्रति कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक, डॉ. रश्मि तिवारी, प्रभा राज, डॉ. अरूणिमा दत्ता, भीमसेन भगत, डॉ. नसीमा बेगम असारी, कमलेश पटेल, सुशील कुमार छात्रे, अतिथि व्याख्याता डॉ. रामजी गर्ग, रामनिवास, शुभम गोयल, पुष्पराज, शिव कुमार, शिवानन्द साकेत, सुश्री अल्पना खलखों, अभिषेक सिंह, थनेन्द्र कश्यम सुमित तिवारी, एवं कार्यालीन स्टाफ मनीष कुमार श्रीवास्तव, पी.एल पटेल, बी.एल. शुक्ला, रामखिलावन गुप्ता, सुमित बड़ा, मीना त्रिपाठी, साधना एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।

जनसंपर्क विभाग की फ़ोटो प्रदर्शनी का किया अवलोकन

छत्तीसगढ़ में सुशासन और विकास की नई परिभाषा विधायक रेणुका सिंह ने गिनाई जिले और राज्य की एक साल की उपलब्धियां

छ.ग. फ्रंटलाइन कोरिया। भरतपुर-सोनहत की विधायक रेणुका सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर राज्य की उपलब्धियों और विकास योजनाओं की जानकारी साझा की।उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन और विकास के क्षेत्र में मिली सफलताओं को रेखांकित किया।विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन को पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाया है। सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। नागरिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है।विधायक ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को अब तक 6530 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है।विधायक ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति दी है। राज्य के 68 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है। युवाओं के लिए रोजगारपरक नई उद्योग नीति लागू की गई है, जिसमें स्वरोजगार और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है।उन्होंने बताया कि तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपए मानक बोरा की गई है। जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से समाज की पहचान को नया आयाम दिया गया है। रेणुका सिंह ने बताया कि बीते एक वर्ष में 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है और 1750 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोला गया और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं को गति दी गई है।उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से कहा कि राज्य में पांच शक्ति पीठों का विकास, बस्तर पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण और भगवान राम से छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक संबंधों को उजागर करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं।उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वय से 31 हजार करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं और कई रेल नेटवर्क विस्तार योजनाओं को मंजूरी मिली है। रेणुका सिंह ने विगत एक साल में कोरिया जिले के उपलब्धि के बारे में बताया कि 93 प्रतिशत लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है, जो राज्य में तीसरे स्थान पर है। सरस्वती सायकिल योजना, महतारी वन्दन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना के मामले में 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बड़ी सफलता अर्जित की है।विधायक ने जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई फ़ोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया, उन्होंने पेपर कतरनों की सराहना भी की। राज्य की जनता और मीडिया का धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार जनता के समर्थन से छत्तीसगढ़ को प्रगति और सुशासन का मॉडल राज्य बनाएगी।प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अपर कलेक्टर श्री अरुण मरकाम, डिप्टी कलेक्टर विनय कश्यप सहित बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि शामिल थे।

जिले के सभी धान खरीदी केंद्र की नियमित की जा रही है निगरानी

छ.ग. फ्रंटलाइन जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशन में विपणन अधिकारी ने विगत दिवस समितियों का औचक निरीक्षण किया गया जहां खरीदी केंद्र में बारदाना कि पर्याप्त व्यवस्था, स्टेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक कांटा में मानक तौल,नमी मापक यंत्र में नमी की जाँच,नोडल अधिकारियों कि समय पर उपस्थिति एवं उनके द्वारा सतत मॉनिटरिंग,धान उपार्जन में दैनिक वृद्धि को ध्यान मे रखते हुए पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था रखें जाने व बिचौलियों की जानकारी मिलने पर तत्काल सूचना देने और अवैध धान जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पंजीकृत किसानों से ही धान खरीदने, किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने की बात कही।

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेसवार्ता कर एक साल पूरा होने पर गिनाया विकास कार्य

छ.ग. फ्रंटलाइन मनेन्द्रगढ विष्णुदेव साय सरकार के एक साल पूरा होने पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने प्रेसवार्ता कर एक साल के विकास कार्यों को गिनाया। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल हेलीकॉप्टर से मनेन्द्रगढ़ पहुंचे और मनेन्द्रगढ़ पहुंचने के बाद कलेक्टर परिसर में अब तक के विकास कार्यों के छायाचित्र का फीता काटकर उदघाटन किया और जिले के अधिकारियों के साथ

अवलोकन किया। इस दौरान सीएमएचओ को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिला अस्पताल में हृदय रोग से पीड़ित बच्चे को गोद में लेने की तस्वीर को जिला अस्पताल में लगवाया जाय । इसके बाद कलेक्टर परिषद के सभाकक्ष मे पत्रकारों से सरकार और अपने विधानसभा होने की बात की। विष्णुदेव साय की सरकार के सुशासन में एक साल छत्तीसगढ़ खुशहाल हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के विकास कार्यों को गिनाने का काम किया साथ ही बस्तर व सरगुजा मे तेजी से विकास का होना बताया वही अपने विधानसभा में हुए विकास कार्यों को भी गिनाया।

कुनकुरी पुलिस की बड़ी कार्यवाही 407 नशीली टेबलेट के साथ मास्टरमाइंड मकसूद आलम गिरफ्तार

छ.ग. फ्रंटलाइन कुनकुरी । पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में जशपुर जिले में नशे के विरूद्ध अभियान के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। सभी थाना प्रभारियों को टीम लगाकर नशीले पदार्थों के बिकी परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि दिनांक 13.12.2024 को मुखबीर से जानकारी मिली कि मकसूद आलम उर्फ मिस्टर निवासी मस्जिद मोहल्ला कुनकुरी का जो कि अवैध नशीली प्रतिबंधित दवाओं का अवैध रूप से कहीं से लाकर लुक छिप कर बिकी करता है तथा आज अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवा टेबलेट बिकी करने हेतु कुनकुरी टाउन में घूम घूम कर ग्राहक तलाश कर रहा है।पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा

थाना प्रभारी कुनकुरी को तत्काल तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये कि कुनकुरी थाना से एक टीम बनाकर तत्काल सूचना की तस्दीक की गई तो मकसूद आलम उर्फ मिस्टर निवासी मस्जिद मोहल्ला कुनकुरी का पंजाब नेशनल बैंक के पास कुनकुरी के पास दिखा जो जो बिना नम्बर की प्लेटिना मोटर सायकल में अपने पास प्लास्टिक थैलानुमा पन्नी रखा था कि घेराबंदी कर उसे पकडा गया तथा उसके द्वारा रखे गये प्लास्टिक थैली व बदन की तलाशी में उसके कब्जे से अवैध रूप से नशीला टेबलेटस्पॉजमो पॉक्सीवान (ट्रामाडोल) नशीला प्रतिबंधित दवा कैप्सुल कुल 407 नग बरामद हुआ जो बिकी करने हेतु अपने कब्जे मे रखना बताया ।नारकोटिक्स एक्ट के वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुये मकसूद आलम उर्फ मिस्टर पिता महमूद आलम उम्र 35 वर्ष साकिन मस्जिद मोहल्ला कुनकुरी के कब्जे से अवैध रूप से रखा हुआ प्रतिबंधित दवा नशीली टेबलेट 407 नग स्पॉजमो पॉक्सीवान, परिवहन में उपयोग किया बिना नम्बर प्लेटिना मोटर सायकल एवं एक विवो कम्पनी का मोबाईल कुल कीमती 30000 करीब का बरामद कर जप्त कर कार्यवाही की गई आरोपी को धारा 21 (बी) नाारकोटिक्स एक्ट के अंर्तगत गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में इसके साथी दिवाकर ताम्रकार एवं ताराबाबा निवासी कुनकुरी को नशीली प्रतिबंधित दवा के साथ पकड़ा गया था जिन पर कार्यवाही की गई थी तब पुलिस को जानकारी मिली थी मकसूद आलम उर्फ मिस्टर नशीली दवा लाने का मास्टर माईंड है और लगातार इसके गतिविधि पर निगाह रखी जा रही थी। यह अभियान लगातार जारी रहेगा ।

जशपुर पुलिस की महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर बड़ी कार्यवाही आरोपी गिरफ्तार.

पुलिस अधीक्षक ने कहा महिला संबंधी किसी भी प्रकार के अपराध में अपराधी के विरुद्ध जशपुर पुलिस द्वारा की जावेगी कड़ी कार्यवाही.

छ.ग. फ्रंटलाइन कुनकुरी। । प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15 नवंबर 2024 को जशपुर जिले के एक थाने में प्रार्थिया ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ एक व्यक्ति द्वारा शादी का प्रलोभन देकर वर्ष 2023 से लगातार उसके साथ दैहिक शोषण किया जा रहा था, जिससे मेरे द्वारा शादी के बारे में पूछने पर अब शादी से इंकार कर रहा है।जिस पर थाने में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(ठ) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। आरोपी अमरदीप तिग्गा के रिपोर्ट दिनांक से फरार होने से जशपुर पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान साइबर सेल की सहायता से आरोपी के लैलूंगा जिला रायगढ़ में होने की जानकारी पर पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह (भा.पु.से.) के दिशा निर्देश व नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लैलूंगा जिला रायगढ़ से आरोपी को हिरासत में लिया गया है।पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह (भा.पु.से.) बताया कि जशपुर पुलिस महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति अत्यंत सजग है, उनके विरुद्ध होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध के अपराधियों के खिलाफ जशपुर पुलिस द्वारा त्वरित, सख्त व कठोर कार्यवाही की जाएगी।इस प्रकरण की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में डीएसपी अजाक/क्राइम भावेश समरथ, उपनिरीक्षक खोम राज सिंह ठाकुर, आरक्षक शिव शंकर, आरक्षक अविनाश लकड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बगीचा के स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण

छ.ग. फ्रंटलाइन जशपुरनगर 14 दिसंबर 2024/कलेक्टर श्री रोहित व्यास के मार्गदर्शन में विगत दिवस आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने के संबंध में बगीचा विकासखंड के स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को मोबाइल ऐप में तकनीकी समस्या आ रही थी उन समस्याओं का निराकरण हेतु जिला से आयुष्मान समन्वयक श्री शिशिर सिंह परमार द्वारा सीएससी बगीचा में संबंधित कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया गया व जिनकी आयुष्मान आईडी नहीं बनी थी उनकी आईडी बनाई गई व तकनीकी समस्या का समाधान किया गया।

बैगा बहुल ग्राम कन्नौज की प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को बांटे गए गर्म कपड़े

छ.ग. फ्रंटलाइन मनेन्द्रगढ़ भरतपुर विकासखंड के बैगा बहुल ग्राम कन्नौज में बढ़ती ठंड को देखते हुए प्राथमिक विद्यालय कन्नौज में शाला प्रबंधन समिति और शिक्षकों के संयुक्त प्रयास से बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। इस पहल में विकासखंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मद इस्माइल खान, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुदर्शन पैकरा, संकुल समन्वयक रमेश पटेल और विद्यालय के सभी शिक्षकों ने भाग लिया। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को स्वेटर और अन्य गर्म कपड़े वितरित किए गए। इस नेक कार्य से बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने गर्म कपड़े पाकर मुस्कुराते हुए अपनी खुशी साझा की। शिक्षकों और अधिकारियों ने भी उनकी हौसला-अफजाई की और आगे भी इस तरह के सहयोग जारी रखने का भरोसा दिलाया।

छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं से संबंधित वितरित किए जा रहे पुस्तक, ब्रोसर, बुकलेट

छ.ग. फ्रंटलाइन जशपुर।। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन का एक वर्ष पूर्ण होने पर जनसंपर्क विभाग जशपुर के द्वारा रणजीता स्टेडियम चौक के पास 13 से 14 दिसंबर 24 तक दो दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिसमें छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी लोगों को दी जा रही है। प्रर्दशनी का अवलोकन करने वाले फरसाबहार विकास खंड के नवीन कुमार , बसंत कांसाबेल विकास खंड के पाकरटोली निवासी श्री रूपेश साय ने बताया कि वे अभी कालेज में पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन करके अच्छा लगा और बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारी भी मिला है। तैयारी करने के लिए योजना से

संबन्धित पुस्तिका भी मिला जिसके उनको अब तैयारी करने में आसानी होगी। पत्थलगांव विकास खंड के जय प्रकाश पैंकरा ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया और खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत अनेक अच्छी योजना संचालित की जा रही है। इसकी जानकारी विस्तार से उनको यहां आकर मिला है। और लोगों को भी इसकी जानकारी देने की बात कही। प्रदर्शनी का अवलोकन जशपुर गिराग के ननकू राम, कुलविंदर, बाबूलाल, कुनकुरी के जावेद, भागलपुर जशपुर के अलका कुजूर ने भी अवलोकन किया।प्रदर्शनी स्थल मे एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी उपलब्धियों की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा पुस्तक, ब्रोसर, बुकलेट का भी वितरण किया जा रहा है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान योजना से लाभान्वित हुए जनजाति परिवारों भी दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना किस तरह से लोगों के पक्के आशियाने को पूरा कर रही है इसे भी प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय का प्रयास से 220 बिस्तर का अस्पताल, 400 केवी विद्युत सब स्टेशन, पर्यटन के क्षेत्र में जशपुर ले रहा नया रूप, एडवेंचर, इको-टूरिज्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई है मायली नेचर कैंप का किया जा रहा है विकास को भी प्रदर्शित किया गया है।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की पहल पर ग्राम चापाटोली में बिजली पुन: हुई बहाल

छ.ग. फ्रंटलाइन जशपुरनगर। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की पहल पर विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने का कार्य सतत रूप से जारी है। इस क्रम में कैंप कार्यालय के निर्देश पर ग्राम चापाटोली, तहसील दुलदुला में बिजली केबल तार जल जाने के वजह से बाधित हुई बिजली को विद्युत विभाग द्वारा ठीक कर दिया गया है। ग्रामीणों ने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।ग्राम चापाटोली के मनोहर राम ने कैंप कार्यालय में आवेदन देकर बताया कि सामुदायिक भवन से एक निजी दुकान तक और हर्राटोली से एक निजी निवास तक का बिजली का तार किसी कारणवश जल गया है। बिजली नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने इसे जल्द ठीक करने की मांग की। कैंप कार्यालय की पहल पर विद्युत विभाग द्वारा तत्काल इसे बदल दिया गया है। इससे बिजली पुन: बहाल हो गई है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व ऑफसेट पुराना पोस्ट ऑफिस रोड दरीपारा अम्बिकापुर (छ.ग.) पिन नं. 497001 से मुद्रित व महलपारा बैकुण्ठपुर से प्रकाशित। संपादक- कमलेश शर्मा